PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 082
दि. 21.07.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

'चलो संसद' मार्च से सुलगी राजधानी, छात्र आंदोलन ने संसद से सड़क तक मचाया सियासी भूचाल

नई दिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर निकला 'चलो संसद' मार्च सोमवार को देश की राजधानी में बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव का कारण बन गया। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन हजारों छात्रों, अभ्यर्थियों, अभिभावकों और विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन ने दिल्ली की सड़कों से लेकर संसद भवन तक माहौल गरमा दिया। एक ओर प्रदर्शनकारी इसे युवाओं के भविष्य की लड़ाई बताते रहे, तो दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल प्रयोग, आंसू गैस और हिरासत जैसी कार्रवाई की। पूरे घटनाक्रम ने शिक्षा व्यवस्था, लोकतांत्रिक विरोध और कानून-व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा आयोजित 'चलो संसद' मार्च का उद्देश्य नीट पेपर लीक, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद तक अपनी आवाज पहुंचाना था। प्रदर्शन की शुरुआत सुबह जंतर-मंतर से हुई, जहां पिछले एक महीने से विभिन्न छात्र संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे। सुबह होते-होते हजारों छात्र वहां एकत्र होने लगे और देखते ही देखते जंतर-मंतर आंदोलन का केंद्र बन गया।

दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संसद भवन के आसपास अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की थी। संसद मार्ग, जनपथ, विजय चौक और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कई मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार एहतियात के तौर पर बंद कर दिए गए, जबकि बैरिकेडिंग कर संसद की ओर जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों को सील कर दिया गया। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार करने का प्रयास करते रहे, जिससे कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़पें हुईं।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनका मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस ने बिना पर्याप्त चेतावनी के लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दावा किया कि कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए, कुछ के सिर फूट गए और कई के हाथ-पैर टूट गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ छात्राओं के साथ पुलिसकर्मियों ने कथित रूप से दुर्व्यवहार किया। उनके अनुसार उन्होंने स्वयं बैरिकेड के पास पुलिस द्वारा छात्रों के साथ कठोर व्यवहार देखा।

हालांकि दिल्ली पुलिस का पक्ष इससे अलग है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने निर्धारित मार्ग और शर्तों का उल्लंघन करते हुए संसद की ओर बढ़ने का प्रयास किया। कई स्थानों पर पथराव किया गया, सरकारी बसों और पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया तथा सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया गया। पुलिस के अनुसार इस झड़प में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के 50 से अधिक जवान घायल हुए हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 65 मेडिको-लीगल केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया।

दिनभर राजधानी के कई हिस्सों में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। संसद मार्ग, जनपथ, कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर के आसपास यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुरक्षा कारणों से कई मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए, जिससे हजारों यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने पड़े।

पुलिस ने शाम तक जंतर-मंतर का प्रदर्शन स्थल खाली करा दिया, लेकिन आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। कई प्रदर्शनकारी कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क, विभिन्न मेट्रो स्टेशनों और आसपास के इलाकों में डटे रहे। देर शाम फिर जंतर-मंतर के आसपास भीड़ जमा होने लगी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी का दौर शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए, जिनमें कहीं प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई दिखाई दी तो कहीं पुलिस वाहनों पर पथराव और तोड़फोड़ के दृश्य सामने आए।

दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें शांगरी-ला होटल के पास कुछ प्रदर्शनकारी कथित रूप से पुलिस वाहन पर पथराव करते दिखाई दिए। वीडियो में लाठी-डंडों से वाहन को नुकसान पहुंचाने के दृश्य भी दिखाई दिए। पुलिस का दावा है कि इस घटना में एक महिला हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हुई हैं।

इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता इसमें विभिन्न वर्गों की भागीदारी रही। स्कूली छात्र, कॉलेज विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी, अभिभावक, सामाजिक कार्यकर्ता और बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कुछ छात्र स्कूल यूनिफॉर्म में पहुंचे, जबकि कुछ ने प्रतीकात्मक रूप से कॉकरोच की वेशभूषा पहनकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है।

जंतर-मंतर पर पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने साफ कहा कि जब तक छात्र प्रतिनिधियों को सांसदों से मिलने का अवसर नहीं मिलेगा या सांसद स्वयं उनसे मिलने नहीं आएंगे, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं की आवाज संसद तक पहुंचनी चाहिए और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।

दूसरी ओर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के तीन युवा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन जारी रहेगा और परीक्षा सुधारों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।

दिनभर के घटनाक्रम के बीच सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत की कोशिश भी हुई। सीजेपी के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में सौरव दास और आशुतोष रांका शामिल थे। संगठन के अनुसार, जेपी नड्डा ने मांगों पर सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा का आश्वासन दिया और समय मांगा। पार्टी ने सोनम वांगचुक की रिहाई, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा प्रभावित अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग दोहराई।

जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जानकारी देते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों की ओर से बातचीत का प्रस्ताव आने के बाद सरकार और प्रतिनिधिमंडल के बीच सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से आंदोलन समाप्त कर सामान्य स्थिति बहाल करने की अपील भी की।

दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन के समानांतर संसद के भीतर भी इस मुद्दे पर तीखी राजनीतिक टकराहट देखने को मिली। मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की आवाज दबा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि संसद देश के युवाओं की भी है और उनकी बात सुनना सरकार की जिम्मेदारी है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में लगातार पेपर लीक की घटनाओं से करोड़ों छात्र प्रभावित हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के सवालों का जवाब देने के बजाय उन पर लाठियां बरसवा रही है। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, वाम दलों और अन्य विपक्षी नेताओं ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए पुलिस कार्रवाई की आलोचना की। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार को युवाओं की बात सुननी चाहिए, न कि उन्हें बलपूर्वक दबाना चाहिए।

पश्चिम एशिया में युद्ध की आंच से वैश्विक अर्थव्यवस्था सुलगी

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में एक बार फिर भड़के सैन्य तनाव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अस्थिरता के दौर में पहुंचा दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव का असर अब केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर दिखाई देने लगा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है, जबकि समुद्री परिवहन की लागत में भी तेज वृद्धि दर्ज की जा रही है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए यह स्थिति कई मोर्चों पर चुनौती बनती दिखाई दे रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में संघर्ष लंबा खिंचता है तो भारत में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, विमान ईंधन (एटीएफ) समेत ऊर्जा उत्पादों की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। इसके साथ ही आयात-निर्यात महंगा होने से उद्योगों की लागत बढ़ेगी और अंततः इसका असर आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। महंगाई, व्यापार घाटा और रुपये पर दबाव जैसी आर्थिक चुनौतियां भी गंभीर रूप ले सकती हैं।

सबसे अधिक चिंता का विषय होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री मार्गों में शामिल है, जहां से खाड़ी देशों का अधिकांश कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस एशिया तथा यूरोप तक पहुंचती है। मौजूदा तनाव के कारण इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कई शिपिंग कंपनियों ने सुरक्षा कारणों से अपने जहाजों का मार्ग बदल दिया है, जिससे उन्हें लंबा समुद्री रास्ता अपनाना पड़ रहा है। परिणामस्वरूप ईंधन की खपत, यात्रा का समय और परिचालन लागत में भारी वृद्धि हुई है।

समुद्री परिवहन क्षेत्र पर संकट लगातार गहराता जा रहा है। युद्ध क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों के लिए जोखिम बीमा (वार रिस्क इंश्योरेंस) का प्रीमियम कई गुना तक बढ़ चुका है। जहाज मालिकों और निर्यातकों को अतिरिक्त सुरक्षा खर्च वहन करना पड़ रहा है। कई मार्गों पर कंटेनर शिपमेंट का खर्च दोगुना तक पहुंच गया है। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार की पूरी लागत प्रभावित हो रही है।

भारतीय निर्यातकों पर भी इसका सीधा असर दिखाई देने लगा है। निर्यात संगठनों के अनुसार कई विदेशी खरीदार अनिश्चितता के कारण नए ऑर्डर देने से बच रहे हैं, जबकि पहले से जारी कई ऑर्डर स्थगित किए जा रहे हैं। जहां ऑर्डर जारी हैं, वहां परिवहन लागत इतनी बढ़ चुकी है कि निर्यातकों का लाभ कम होता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर, मध्य एशियाई देशों के लिए भेजे जाने वाले कंटेनरों की लागत पहले की तुलना में दोगुनी से अधिक हो गई है। इससे भारत के वस्त्र, इंजीनियरिंग, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य निर्यात क्षेत्रों पर दबाव बढ़ रहा है।

ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का असर केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता। जब ईंधन महंगा होता है तो परिवहन लागत बढ़ती है, जिससे खाद्यान्न, फल-सब्जियां, दवाइयां, निर्माण सामग्री, उपभोक्ता वस्तुएं और औद्योगिक उत्पाद भी महंगे होने लगते हैं। यही कारण है कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को महंगाई का सबसे बड़ा कारक माना जाता है।

भारत अपनी कुल तेल आवश्यकता का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी सीधे देश के आयात बिल को प्रभावित करती है। यदि लंबे समय तक तेल महंगा रहता है तो चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है। साथ ही विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ने से रुपये की विनिमय दर भी प्रभावित हो सकती है। रुपये के कमजोर होने पर अन्य आयातित वस्तुएं भी महंगी हो जाएंगी, जिससे अर्थव्यवस्था पर दोहरा दबाव पड़ेगा। उद्योग जगत का कहना है कि मौजूदा हालात में उर्वरक, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, रसायन, विमानन, लॉजिस्टिक्स और शिपिंग जैसे क्षेत्रों पर सबसे अधिक असर पड़ सकता है। कच्चे माल और परिवहन लागत बढ़ने से उत्पादन महंगा होगा, जिसका असर घरेलू बाजार में कीमतों के रूप में दिखाई देगा। यदि स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो कई उद्योगों की उत्पादन योजनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार भी युद्ध की आशंका से लगातार अस्थिर बने हुए हैं। निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव लगातार जारी है।

डेंगू से जंग में भारत को बड़ी कामयाबी

नई दिल्ली। डेंगू जैसी गंभीर और तेजी से फैलने वाली बीमारी के खिलाफ भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। लंबे समय से जिस प्रभावी वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था, उसे अब देश में उपयोग की मंजूरी मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने जापान की प्रमुख बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी ताकेदा द्वारा विकसित डेंगू वैक्सीन 'क्यूडेंगा' (QDENGA/TAK-003) के भारत में उपयोग को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही भारत उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जहां डेंगू की रोकथाम के लिए प्रमाणित वैक्सीन उपलब्ध है।

यह मंजूरी इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अब 4 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोग बिना किसी प्री-वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग (पूर्व जांच) के यह वैक्सीन लगवा सकेंगे। यानी टीका लगवाने से पहले यह जांच कराने की आवश्यकता नहीं होगी कि व्यक्ति को पहले कभी डेंगू हुआ है या नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार इससे टीकाकरण की प्रक्रिया सरल होगी और अधिक से अधिक लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जा सकेगी।

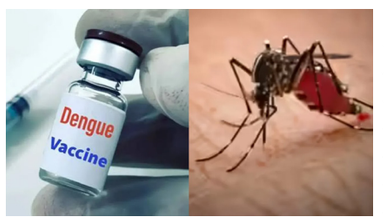

भारत में हर वर्ष मानसून और उसके बाद डेंगू के मामलों में तेजी से वृद्धि होती है। हजारों लोग अस्पतालों में भर्ती होते हैं और अनेक गंभीर मरीजों की जान तक चली जाती है। ऐसे में प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध होना सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यदि टीकाकरण का दायरा व्यापक हुआ तो आने वाले वर्षों में डेंगू के गंभीर मामलों, अस्पतालों पर बढ़ते दबाव और मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

इस वैक्सीन को मंजूरी व्यापक वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद दी गई है। ताकेदा के वैश्विक क्लीनिकल डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत फेज-1, फेज-2 और फेज-3 सहित कुल 19 क्लीनिकल ट्रायल किए गए, जिनमें दुनिया भर के 28 हजार से अधिक स्वयंसेवियों ने भाग लिया। इन परीक्षणों के आधार पर वैक्सीन की सुरक्षा, प्रभावशीलता और विभिन्न आयु वर्गों में इसकी उपयोगिता का मूल्यांकन किया गया। इन्हीं परिणामों के आधार पर भारतीय नियामक संस्था ने इसके उपयोग की अनुमति प्रदान की है। क्यूडेंगा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे डेंगू वायरस के चारों प्रमुख सीरोटाइप (DEN-1, DEN-2, DEN-3 और DEN-4) से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। भारत में इन चारों प्रकार के वायरस अलग-अलग क्षेत्रों में सक्रिय रहते हैं और यही कारण है कि डेंगू की रोकथाम चुनौतीपूर्ण बनी रहती है। कंपनी का दावा है कि यह वैक्सीन सभी प्रमुख सीरोटाइप के विरुद्ध सुरक्षा देने की क्षमता रखती है, जिससे गंभीर संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को कम किया जा सकता है।

वैक्सीन दो डोज में दी जाएगी। प्रत्येक डोज 0.5 मिलीलीटर की होगी और इसे त्वचा के नीचे (सबक्यूटेनियस) इंजेक्शन के माध्यम से लगाया जाएगा। पहली और दूसरी डोज के बीच तीन महीने का अंतर रखा जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों डोज समय पर लेना आवश्यक होगा, ताकि शरीर में पर्याप्त प्रतिरक्षा विकसित हो सके।

हालांकि यह वैक्सीन जापान की ताकेदा कंपनी द्वारा विकसित की गई है, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन भारत में ही किया जाएगा। इसके लिए ताकेदा ने हैदराबाद स्थित प्रमुख वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई के साथ उत्पादन साझेदारी की है।

पासपोर्ट-वीजा सेवाओं में नहीं आएगी रुकावट, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत,टेंडर रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले में दखल से इनकार, नई निविदा पूरी होने तक मौजूदा व्यवस्था जारी रखने की अनुमति

नई दिल्ली। विदेशों में भारतीय नागरिकों को मिलने वाली पासपोर्ट, वीजा और अन्य कॉन्सुलर सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत अबू धाबी, कुवैत, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा स्थित भारतीय मिशनों में कॉन्सुलर, पासपोर्ट और वीजा सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि नई टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक इन सेवाओं में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आना चाहिए और इसके लिए केंद्र सरकार आवश्यक अंतरिम व्यवस्था कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विदेशों में रह रहे लाखों भारतीय नागरिकों, प्रवासी कामगारों, छात्रों, व्यापारियों और अन्य आवेदकों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने माना कि पासपोर्ट और वीजा जैसी सेवाएं अत्यंत आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं हैं और इनमें किसी भी प्रकार की बाधा से बड़ी संख्या में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब तक नई निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक मौजूदा व्यवस्था के माध्यम से सेवाओं का संचालन जारी रखा जाना चाहिए।

मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि न्यायालय का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के दैनिक कार्य प्रभावित न हों। अदालत ने कहा कि नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की निरंतरता सर्वोपरि है और प्रशासनिक या संविदात्मक विवादों का असर आम लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने विदेश मंत्रालय (एमईए) और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को यह अनुमति दी कि वे नई टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक अस्थायी व्यवस्था के माध्यम से कॉन्सुलर, पासपोर्ट और वीजा सेवाओं का संचालन जारी रखें। अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतरिम व्यवस्था केवल सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से होगी और इससे भविष्य की टेंडर प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय द्वारा चार भारतीय मिशनों—अबू धाबी, कुवैत, सिंगापुर और कैनबरा—में कॉन्सुलर एवं पासपोर्ट सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए जारी निविदा प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सरकार का तर्क था कि यदि टेंडर प्रक्रिया रद्द रहने के कारण सेवाएं प्रभावित हुईं तो विदेशों में भारतीय नागरिकों को गंभीर परेशानी उठानी पड़ सकती है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और केंद्र की अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही अदालत ने यह संतुलित व्यवस्था दी कि नई निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक सेवा वितरण बाधित न हो। न्यायालय ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है तथा नागरिकों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

विदेश मंत्रालय के लिए यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि विदेशों में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के माध्यम से प्रतिदिन बड़ी संख्या में पासपोर्ट नवीनीकरण, नए पासपोर्ट, वीजा, ओसीआई कार्ड, दस्तावेजों के सत्यापन, जन्म-मृत्यु पंजीकरण और अन्य कॉन्सुलर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं में किसी भी प्रकार की रुकावट का सीधा असर लाखों भारतीय नागरिकों और विदेशी आवेदकों पर पड़ सकता था।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में न्यायिक समीक्षा और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। एक ओर अदालत ने टेंडर प्रक्रिया को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया, वहीं दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित किया कि प्रशासनिक विवाद के कारण आम नागरिकों को असुविधा न हो। अब विदेश मंत्रालय और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को नई टेंडर प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में तेजी से काम करना होगा। इसके बाद नई एजेंसी के चयन और अनुबंध की प्रक्रिया पूरी होने पर इन भारतीय मिशनों में नियमित व्यवस्था लागू की जाएगी। तब तक अदालत के निर्देशानुसार वर्तमान सेवाएं बिना किसी व्यवधान के जारी रहेंगी, जिससे विदेशों में भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट, वीजा और अन्य कॉन्सुलर सेवाएं पहले की तरह मिलती रहेंगी।

संपादकीय

विश्वसनीय हो स्क्रैपिंग

हरियाणा में पुराने वाहनों को चलन से बाहर करने के लिये सरकार ने जिन प्रोत्साहन स्कीमों की घोषणआ की है, वह समय की जरूरत है। हरियाणा सरकार ने वैज्ञानिक तरीके से गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिये पांच प्रोत्साहन योजनाएं शुरू करने का फैसला किया है। जो पुरानी गाड़ियों को देखने के नजरिये में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती हैं। दरअसल, पुरानी हो चुकी गाड़ियों को सिर्फ कबाड़ नहीं माना जाना चाहिए, यदि उनका कायदे से निस्तारण हो तो आर्थिक लाभ के साथ पर्यावरण की रक्षा भी की जा सकती है। कुछ लोग अपने वाहन की देखभाल इतने कायदे से करते हैं कि उसे कबाड़ कहना, उनकी भावना को ठेस पहुंचाने जैसा है। दरअसल, अब राज्य सरकार की नई पॉलिसी इन वाहनों को कबाड़ मानने के बजाय, उन्हें रीसाइकिल होने वाले मेटीरियल, ग्रीन जॉब्स प्रदाता और साफ हवा के स्रोत के रूप में दर्शाती है। निस्संदेह,यह कदम अर्थव्यवस्था में योगदान की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। दरअसल, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, भारत में 3.4 करोड़ से अधिक पुराने वाहन हैं। जिनमें दो करोड़ दो पहिया और 1.2 करोड़ चार-पहिया वाहन शामिल हैं। इनमें बड़ी संख्या में वाहन अभी सड़कों में चलाए जा रहे हैं। दरअसल, पुरानी गाड़ियां नये मॉडल की तुलना में काफी अधिक मात्रा में पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती हैं। जिससे एक ओर वायु प्रदूषण बढ़ता है, वहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।

दरअसल, वैज्ञानिक स्क्रैपिंग से कीमती स्टील, एल्युमीनियम, तांबा और प्लास्टिक को दोबारा से हासिल किया जा सकता है। जिससे नये कच्चे माल पर निर्भरता कम हो सकती है। साथ ही उत्पादन में ऊर्जा की खपत भी घटती है। दरअसल, हरियाणा सरकार की प्रोत्साहन योजनाएं - कैपिटल सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी की वापसी,एसजीएसटी रिफंड, ब्याज में मदद और स्किल डेवलपमेंट- अधिकृत स्क्रैपिंग और रीसाइक्लिंग सुविधाओं में निवेश को आकर्षित करने के लिये बनायी गई है। लेकिन इस पॉलिसी की सफलता सिर्फ इंडस्ट्री की भागीदारी पर ही निर्भर नहीं करेगी। गाड़ी मालिकों को भी स्वेच्छा से इसमें शामिल करने के लिये प्रोत्साहित करना होगा। तमाम परिवारों के लिये, पुरानी गाड़ी सिर्फ घटती कीमत वाली संपत्ति नहीं है, बल्कि रोजी-रोटी का जरिया भी होती है। जब तक उन्हें उचित मुआवजा,आसान प्रक्रियाएं और अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर्स तक सुविधाजनक पहुंच नहीं मिलेगी, तब तक कई लोग अनौपचारिक सेक्टर पर ही निर्भर रहेंगे। ऐसे में गैर-कानूनी तौर पर गाड़ियों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। वहीं लोगों को जागरूक बनाने और स्वेच्छा से स्क्रैपिंग के लिये प्रोत्साहित करने की जरूरत है। निस्संदेह, सिर्फ नियम बनाने से हवा को साफ नहीं किया जा सकता। इसके लिये ऐसी नीतियां बनें, जो आर्थिक रूप से व्यावहारिक,पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक रूप से निष्पक्ष हों। यदि हरियाणा सरकार की पहल लक्ष्यों के बीच संतुलन बना पाती है तो यह टिकाऊ गतिशीलता के लिये एक राष्ट्रीय मॉडल बन सकता है। फिर बीते कल की गाड़ियां आने वाले कल के लिये संसाधन बन सकती हैं।

सोनम वांगचुक के आंदोलन की अनदेखी का प्रश्न

> "निस्संदेह नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जिम्मेदारी तय करने व कार्रवाई को लेकर सोनम वांगचुक के आमरण अनशन पर अलग-अलग राय हो सकती है। एक तरफ उनकी सेहत पर चिंता जताती याचिका व विपक्ष की सलाह। दूसरी ओर राजनीतिक चुप्पी। वहीं अनुच्छेद 370, परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर दलों के भीतर मतभेद जारी हैं। संसद का परिदृश्य जोड़तोड़ से बदल रहा है, जबकि वांगचुक का संघर्ष नजरअंदाज सा है।

दिल्ली के बीचों-बीच जंतर-मंतर से बस थोड़ी ही दूर, जहां सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे, भारत की संसद है जो जल्द ही शुरू होने वाले मॉनसून सत्र की तैयारी कर रही थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर वांगचुक का अनशन 21वें दिन में प्रवेश कर गया था। उसके दो दिन पहले एक जनहित याचिकाकर्ता ने कहा था कि अगर उन्हें जल्द ही कुछ खाने को नहीं मिला, तो उनका जीवन संकट में पड़ सकता है। एक मेडिकल टीम वहां मौजूद रही और विपक्ष के कई नेता सोनम से हड़ताल खत्म करने को कह रहे थे ; उनका कहना था कि उन्होंने अपनी बात रख दी है, लेकिन दिल्ली के दिल में भारी सन्नाटा पसरा रहा। क्या सोनम वांगचुक को उनके हालात पर छोड़ दिया जाना चाहिये? आख़िरकार, किसी ने उनसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग करते हुए आमरण अनशन करने के लिए नहीं कहा। कुछ लोग कहेंगे कि इस हड़ताल में दबाव बनाने की नीति जैसा कुछ है, तो कुछ इसे ताकतवर लोगों की दुनिया में जनता की निराशा की पुकार मानेंगे। निश्चित रूप से, वांगचुक और उनके साथियों का मानना है कि नीट परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी के लिए किसी को तो ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, वे गड़बड़ियां जिन्हें टाला जा सकता था और जिसने लाखों छात्रों को प्रभावित किया है। कुछ लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए-वरना इतने हंगामे और गुस्से का क्या मतलब था अगर इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला?

जंतर-मंतर पर वांगचुक के धरना स्थल (अब पुलिस हिरासत में अस्पताल में उपचाराधीन) के पास ही, मॉनसून सत्र की शुरुआत वाले दिन जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार द्वारा राज्य का दर्जा बहाल करने से इनकार करने के विरोध में एक दिन का प्रदर्शन करने की योजना बना रहे थे। हालांकि उमर को तब तक प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली थी। इतना ही नहीं,श्रीनगर से उनकी पार्टी के सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने उमर पर अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए लड़ने के अपने वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया। मेहदी गरजते हुए कहते हैं कि कश्मीर के लिए विशेष दर्जा, पूर्ण राज्य के दर्जे से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इल्जाम मौसम को दिया जा सकता है, गर्मी इतनी है कि तल्खियां बढ़ी हुई हैं, खासकर जब बारिश नहीं हो। शायद देवता नाराज़ हैं। फिर, अयोध्या में भी चोरी की घटना हुई है। तो क्या मेहदी की नाराज़गी यह संकेत देती है कि वे उमर से इतने नाराज़ हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी दो फाड़ हो सकता है? या हो सकता है कि मेहदी सही समय का इंतज़ार कर रहे हों और वंशवाद का पासा पलटने की उम्मीद पाले हैं। या फिर वे नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही बने रहें, लेकिन जब भी भाजपा परिसीमन बिल लाने की योजना बनाए, तो उसके पक्ष में मतदान करें। इस बिल का मकसद विस्तारित संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा तय करना है- और यह समझने में कोई गलती न रहे कि इस बिल का मकसद चुनाव क्षेत्रों का नए सिरे से गठन करना है, जिससे भारत में मतदान का तरीका बदलेगा और लोकसभा की संरचना में भी बुनियादी बदलाव आएगा।

संविधान में इतना बड़ा बदलाव करने के लिए, संविधान को सरसरी तौर पर पढ़कर भी आप समझ सकते हैं, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को दो-तिहाई बहुमत की ज़रूरत है- यानी निचले सदन की 543 सीटों में से 360 सीटें, जबकि अभी उनके पास 293 सीटें हैं। अगर वे उस बिल को दोबारा लाना चाहते हैं जो पिछले ही अप्रैल में सदन में गिर गया था, तो उन्हें 67 और सांसदों का साथ चाहिए होगा। और जैसा कि महान चाणक्य ने कहा था, प्यार, जंग और राजनीति में सब कुछ जायज़ है। इसीलिए टीएमसी की टूटन उनके काम आ रही है -28 में से 20 सांसदों ने एक निर्दलीय पार्टी बना ली है जो बाहर से भाजपा का समर्थन करेगी;साथ ही शिवसेना (यूबीटी) का भी बुरा हाल है, जहां नौ में से छह सांसद पार्टी छोड़कर शिवसेना के ही भाजपा-समर्थक एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं; वहीं शरद पवार की एनसीपी में भी यह डर बना हुआ है कि अगर उन्होंने परिसीमन बिल के पक्ष में वोट नहीं दिया तो पार्टी खत्म हो जाएगी।

इस तरह, भले ही मॉनसून के बादल नहीं बरसे, लेकिन 18वीं लोकसभा की फिज़ा काफी हद तक बदल चुकी है। जब मॉनसून सत्र शुरू होगा, तो यह उस लोकसभा से बिल्कुल अलग दिखेगी जिसे दो साल पहले हम लोगों ने चुना था, और यह सब बिना किसी चुनाव के हो गया। कुछ राज्यों में,मसलन, जम्मू-कश्मीर में, स्थिति आसान है। राज्य की कुल संसदीय 5 सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सिर्फ़ 2 सीटें हैं- 2 सीटें भाजपा के पास हैं और एक सीट बारामूला के इंजीनियर राशिद के पास है, जो निर्दलीय सांसद हैं। अगर मेहदी हाथ मिलाने को राजी हो जाएं और इंजीनियर राशिद को मनाया जा सके-क्योंकि 21वीं सदी में कौन नहीं लैंगिक समानता के पक्ष में होना चाहेगा? ध्यान रहे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने राशिद को संसद में शामिल होने की इजाज़त चंद दिन पहले ही दी है।

शायद अब समय आ गया है कि आप अपनी पसंदीदा किताब 'जूलियस सीज़र' को फिर से पढ़ें। बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस नेता मदन मित्रा- जिन्होंने कभी ममता बनर्जी के प्रति वफादारी की कसम खाई थी और टीएमसी से अलग हुए गुट के नेता रिताब्रत बनर्जी को ऐसी गालियां दी थीं जिन्हें सुनकर शरम आ जाए-उन्होंने इसके एक दिन बाद ही पाला बदल लिया और रिताब्रत बनर्जी के साथ चले गए। इससे मुझे उस किस्से की याद हो आई कि क्यों पंजाब के आम आदमी पार्टी के सांसद चुपचाप खिसक लिए। (वे तो बस हमेशा खुशी-खुशी जीवन जीना चाहते हैं)। मित्रा इस बात से इनकार करते हैं कि उनके पाला बदलने के पीछे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके परिवार से पूछताछ किए जाने वाले तथ्य से कोई संबंध है। तृणमूल के जो कुछ सांसद बचे हैं, उनका कहना है कि ईडी बंगाल में काफी व्यस्त है। निश्चित रूप से, ईडी पंजाब में भी सक्रिय है और कथित रूप से धीरे-धीरे एक-एक करके भ्रष्टाचार को खत्म कर रही है- हाल ही में आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा पर मोबाइल फोनों से जुड़े एक बड़े घोटाले का आरोप लगा है।

जहां तक शरद पवार की बात है तो अगर वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगले 24 घंटों में क्या होगा और क्या उनके हाथ में एनसीपी का बचा-खुचा छोटा सा हिस्सा भी रह पाएगा या नहीं, तो उमर अब्दुल्ला ने सामने आकर भाजपा पर उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विधायकों को पाला बदलने के लिए 20-30 करोड़ रुपये की पेशकश की जा रही है। जवाब में भाजपा ने उन्हें 100 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजा है। सोनम वांगचुक का जंतर-मंतर पर अनशन जारी रहा, (अब वे पुलिस हिरासत में अस्पताल में उपचाराधीन हैं) अपने आस-पास चल रही राजनीतिक गतिविधि से बेअसर। सत्याग्रह के वास्तविक प्रदर्शन को देखकर हैरान देश के बाकी हिस्सा इस व्यक्ति की ओर ध्यान देने को मजबूर है- आखिर वह कौन हैं? और अगर उनके शरीर में कुछ भोजन न गया तो क्या उनकी जान जा सकती है?

जहां तक राहुल गांधी का प्रश्न है तो कांग्रेस पार्टी के सबसे ताकतवर नेता के बारे में एक बात तो ज़रूर कही जा सकती है। तीन हफ़्ते की गर्मियों की छुट्टियों से लौटने के बाद, उनमें और भाजपा में एक बात साफ़ तौर पर समान है - दोनों के पास सोनम वांगचुक पर कहने को कुछ नहीं है।

प्रेरणा

संकल्प की शक्ति: जब सपना केवल कल्पना नहीं, जीवन का लक्ष्य बन जाता है

मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने और समय बिताने के लिए नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कोई न कोई ऐसा सपना अवश्य होता है, जो उसे सामान्य भीड़ से अलग पहचान दिला सकता है। कोई वैज्ञानिक बनने का सपना देखता है, कोई कलाकार, कोई शिक्षक, कोई सफल उद्यमी तो कोई समाज की सेवा करने वाला व्यक्तित्व। लेकिन केवल सपना देख लेना ही पर्याप्त नहीं होता। सपनों को साकार करने के लिए जिस सबसे महत्वपूर्ण तत्व की आवश्यकता होती है, वह है दृढ़ संकल्प। बिना संकल्प के सपना केवल एक सुंदर कल्पना बनकर रह जाता है, जबकि संकल्प उसे वास्तविकता में बदलने की दिशा देता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के जितने भी महान आविष्कार, महान संस्थान और महान व्यक्तित्व बने हैं, उनकी शुरुआत किसी न किसी व्यक्ति के मन में जन्मे एक छोटे से सपने से हुई थी। अंतर केवल इतना था कि उन्होंने अपने सपनों को परिस्थितियों के भरोसे नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें पूरा करने का संकल्प लिया।

विश्व प्रसिद्ध उद्यमी और मनोरंजन जगत में क्रांति लाने वाले वॉल्ट डिज़्नी का जीवन इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। एक समय ऐसा था जब वे अपने सपनों को आकार देने के लिए दिन-रात संघर्ष कर रहे थे। जब डिज़्नीलैंड का निर्माण कार्य चल रहा था, तब यह परियोजना बहुत बड़ी और जोखिम भरी मानी जा रही थी। करोड़ों रुपये खर्च हो रहे थे और कई लोगों को यह विश्वास नहीं था कि इतनी विशाल योजना सफल हो पाएगी। इसी दौरान एक पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया कि यदि इतनी बड़ी परियोजना असफल हो गई तो क्या होगा? यह प्रश्न किसी भी व्यक्ति को चिंता में डाल सकता था, लेकिन वॉल्ट डिज़्नी के उत्तर ने यह सिद्ध कर दिया कि सफलता पहले मन में जन्म लेती है, उसके बाद संसार में दिखाई देती है। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा कि जो लोग असफलता के डर से सपने देखना ही छोड़ देते हैं, वे कभी कुछ नया नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पहले अपने सपने को अपनी कल्पना में साकार होते हुए देख लिया है, अब उसे वास्तविकता में बदलना केवल समय की बात है। यह उत्तर केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि जीवन का ऐसा दर्शन था जो हर व्यक्ति को प्रेरणा देता है। वर्षों तक लगातार मेहनत, धैर्य, संघर्ष और विश्वास के बाद वही डिज़्नीलैंड दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल हो गया। आज वहां हर वर्ष करोड़ों लोग पहुंचते हैं और वॉल्ट डिज़्नी का सपना पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन चुका है।

यह घटना हमें सिखाती है कि सफलता का पहला चरण हमारी सोच होती है। यदि मन में यह विश्वास हो कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। दूसरी ओर यदि शुरुआत से ही मन में असफलता का भय बैठ जाए, तो व्यक्ति पहला कदम उठाने से पहले ही हार मान लेता है। वास्तव में सपने देखने वाले और उन्हें पूरा करने वाले लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि सपने देखने वाला केवल कल्पना करता है, जबकि संकल्प लेने वाला उसी कल्पना को अपनी दिनचर्या, अपने परिश्रम और अपने निर्णयों का हिस्सा बना लेता है।

जीवन में अनेक बार परिस्थितियां हमारे विरुद्ध दिखाई देती हैं। आर्थिक कठिनाइयां, संसाधनों की कमी, समाज की आलोचना, परिवार की अपेक्षाएं और बार-बार मिलने वाली असफलताएं व्यक्ति का मनोबल तोड़ने का प्रयास करती हैं। ऐसे समय में यदि संकल्प कमजोर पड़ जाए तो सपना भी धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि संकल्प अडिग रहे, तो वही कठिनाइयां व्यक्ति को और अधिक मजबूत बना देती हैं। पर्वत की ऊंचाई हमेशा चुनौतीपूर्ण होती है, फिर भी पर्वतारोही शिखर तक पहुंचते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट होता है। समुद्र की गहराई भय पैदा करती है, फिर भी गोताखोर उसमें उतरते हैं क्योंकि उन्हें अपने उद्देश्य पर विश्वास होता है। ठीक उसी प्रकार जीवन के बड़े सपनों को भी साहस, धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है।

आज के समय में हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित तो हो जाते हैं, लेकिन उनके संघर्ष को भूल जाते हैं। सोशल मीडिया और आधुनिक जीवनशैली ने सफलता का चमकदार रूप तो दिखाया है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, असफलताएं और वर्षों का धैर्य बहुत कम दिखाई देता है। यही कारण है कि कई लोग थोड़ी सी कठिनाई आने पर अपने लक्ष्य बदल देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि महान उपलब्धियां कभी भी एक दिन में प्राप्त नहीं होतीं। वे छोटे-छोटे प्रयासों, निरंतर सीखने और हार न मानने की आदत से जन्म लेती हैं।

संकल्प का अर्थ केवल यह कहना नहीं है कि मैं सफल बनूंगा। संकल्प का वास्तविक अर्थ है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, मैं अपने लक्ष्य की दिशा में प्रयास करना नहीं छोड़ूंगा। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहता है, तब उसका हर दिन उसे मंजिल के थोड़ा और निकट ले जाता है। यही कारण है कि सफल लोग परिणाम की चिंता कम करते हैं और अपने प्रयासों पर अधिक ध्यान देते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि यदि प्रयास सही दिशा में लगातार जारी रहे, तो सफलता देर से ही सही, अवश्य मिलेगी। भारतीय संस्कृति में भी संकल्प का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत संकल्प के साथ की जाती है। इसका अर्थ केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह मन को लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित करने की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति पूरे मन, बुद्धि और विश्वास के साथ किसी उद्देश्य को स्वीकार कर लेता है, तब उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि एक दिशा में केंद्रित हो जाती है। यही एकाग्रता उसे असाधारण उपलब्धियां दिलाती है।

महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। उस समय यह सपना असंभव माना जाता था, लेकिन उनके संकल्प ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने साधारण परिवार से निकलकर वैज्ञानिक बनने का सपना देखा और उसे अपने संकल्प से पूरा किया। अनेक खिलाड़ियों, वैज्ञानिकों, लेखकों और उद्यमियों की जीवन यात्रा भी यही बताती है कि सफलता का आधार केवल प्रतिभा नहीं, बल्कि अटूट संकल्प होता है।

हर व्यक्ति को अपने जीवन में यह निर्णय लेना चाहिए कि वह केवल परिस्थितियों का इंतजार करेगा या अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वयं आगे बढ़ेगा। यदि लक्ष्य स्पष्ट है, संकल्प मजबूत है और मेहनत निरंतर है, तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। असफलता केवल यह बताती है कि प्रयास की दिशा या तरीका बदलने की आवश्यकता है, न कि सपना छोड़ देने की। जो लोग गिरकर भी उठते हैं, वही अंततः इतिहास रचते हैं।

वॉल्ट डिज़्नी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि दुनिया पहले हमारे सपनों पर संदेह कर सकती है, लेकिन यदि हमारा संकल्प अडिग हो तो एक दिन वही दुनिया हमारी सफलता की कहानी सुनाती है।

भारतीय रेलवे में नई हाइड्रोजन क्रांति, प्रधानमंत्री ने कई रेलवे स्टेशनों का भी दिया उपहार

जुलाई 17, 2026 का दिन भारतीय रेलवे के लिए एक स्मरणीय दिन बन गया है क्योंकि इस दिन रेल यातायात में विकसित भारत के नये युग का सूत्रपात हुआऔर भा रत को हाइड्रोजन ट्रेन का उपहार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया। अब भारत उन चुनिन्दा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन हो रहा है।अभी तक जर्मनी, फ्रांस और चीन जैसे देश ही इस प्रकार की ट्रेनों का संचालन कर रहे थे। जींद-सोनीपत मार्ग पर चलने वाली यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली 10 कोच और 3,200 हार्स पावर क्षमता वाली दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों मे शामिल है। यह ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलने वाली इस ट्रेन में हाइड्रोजन से बिजली बनाई जाती है जिससे ट्रेन संचालित होती है। इस प्रक्रिया में केवल जलवाष्प निकलती है इसलिए इससे शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है। यह ट्रेन डीजल ट्रेनों की तुलना में प्रदूषण नहीं फैलाती, आवाज भी कम करती है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करती है। इसके लिए पारपंरिक इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तरह मार्ग पर ओवरहेड बिजली लाईन की जरूरत भी नहीं होती क्योकि बिजली ट्रेन के भीतर ही तैयार होती है। ऐसी ट्रेनों के संचालन से कोयला आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता कम होगी।

यह 10 कोच वाली दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेनों में शामिल है। यह अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ट्रेन है जो बाहर से देखने में तो साधारण ट्रेनों की तरह ही लगती है किन्तु जब यात्री ट्रेन के कोच में बैठकर यात्रा करते हैं तो उन्हें एक अलग प्रकार की सुखद अनुभूति होती है। ट्रेन में आधुनिक सुरक्षा प्रणाली, हाइड्रोजन लीक डिटेक्शन सिस्टम और विशेष फ्यूल सेल तकनीक का उपयोग किया गया है। इस ट्रेन में यात्रियों के लिए टिकट का मूल्य 5 से 25 रुपए तक रखा गया है ताकि आम से खास तक सभी वर्ग के लोग इस पूर्ण रूप से स्वदेशी तथा प्रदूषण रहित ट्रेन की आरामदायक यात्रा का लाभ उठा सकें। भारतीय रेलवे की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच 89 किमी प्रतिदिन दो राउंड ट्रिप यानी कुल 356 किमी का सफर तय करेगी। यह हाइड्रोजन ट्रेन जींद सिटी, गोहाना, पांडु पिंडारा, ललित खेड़ा, भंभेवा, इसापुर खेड़ी, बुटाना, खंडराई, राबरा, लाथ, मोहाना और सोनीपत स्टेशन पर रुकेगी।

भारत की स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन अन्य देशों की तुलना में सबसे कम लागत मात्र 136 करोड़ रुपए में बनी है। ट्रेन की सामान्य ऑपरेशनल स्पीड 75 किमी प्रति घंटा होगी। ट्रायल रन के दौरान इसने 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार प्राप्त की थी। यह ट्रेन एक घंटे में 90 किमी का सफर तय कर सकती है। जबकि कई पुराने डीजल इंजन वाली ट्रेनों को इतनी दूरी तय करने में लगभग दो घंटे लग जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे में व्यापक बदलाव लाने का संकल्प लिया था जो अब धरातल पर उतरता दिख रहा है। भारतीय रेलवे आगामी वर्षों में और भी आधुनिक बनने की तैयारी कर रहा है। सरकार का लक्ष्य व संकल्प भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित, तेज और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है यह हाइड्रोजन ट्रेन उसी लक्ष्य की दिशा में ले जाने वाली पहल है।

संक्षिप्त इतिहास - भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के बीच चलाई गई थी। यह ट्रेन 34 किमी की दूरी तय करती थी इसमें 14 डिब्बे थे1960 में भारतीय रेलवे ने डीजल इंजनों को अपनाना शुरू किया। इन इंजनों की मदद से लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ। मालगाड़ियों की क्षमता बढ़ी और रेलवे का विस्तार पहले की तुलना में तीव्रगति से हुआ। इसके पश्चात रेलवे में विद्युतीकरण का युग आया जिसमें बिजली से चलने वाले इंजन डीजल की तुलना में अधिक तीव्र ,कम प्रदूषण फैलाने वाले और ऊर्जा की दृष्टि से अधिक किफायती सिद्ध हुए। अब समय पूरी तरह से बदल चुका है। अब यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए बेहतर तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, वंदेभारत एक्सप्रेस जैसी हाईस्पीड ट्रेनों,आधुनिक कोच, आटोमेटिक सिग्नल सिस्टम, कवच सुरक्षा प्रणाली, डिजिटल टिकटिंग और बेहतर स्टेशन सुविधाएं रेलवे को नई पहचान दे रही हैं। आगामी समय में बुलेट ट्रेनों की रफ्तार भी भारतीय जनमानस देखने वाला है। केवल यात्रियों के लिए ही नहीं भारतीय रेल अब माल ढुलाई के लिए भी आधुनिक ट्रेनों का संचालन कर रही है।

हाइड्रोजन ट्रेन के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जींद और पंजाब के जालंधर से रेलवे की विकास व बदलाव की कहानी बताई और साथ ही कांग्रेस सहित समस्त विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए राजनैतिक संदेश भी दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो काम आज हो रहे हैं वो काम तो 30 -40 वर्ष पहले ही हो जाने चाहिए थे लेकिन पहले की सरकारों में यह काम प्राथमिकता में थे ही नहीं। इस पर पहले की सरकारें चर्चा ही नहीं करती थी। 2014 के बाद भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1300 स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है आज ऐसे ही 75 स्टेशनों का लोकार्पण हुआ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अमृतसर -वाराणसी के बीच चलने वाली संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई।

अभियान

आस्था का वह विराम, जो मनुष्य को स्वयं से मिलने का अवसर देता है

भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां प्रत्येक पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित, अनुशासित और अर्थपूर्ण बनाने का माध्यम भी है। हमारे ऋषि-मुनियों ने समय, ऋतु, प्रकृति और मानवीय जीवन के बीच ऐसा अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया कि प्रत्येक उत्सव अपने भीतर गहरा आध्यात्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक संदेश समेटे हुए है। इन्हीं महान परंपराओं में देवशयनी एकादशी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह वह पावन तिथि है, जब भगवान श्रीहरि विष्णु के योगनिद्रा में जाने की मान्यता है और इसी दिन से आरंभ होता है चातुर्मास, जो भारतीय आध्यात्मिक जीवन का सबसे गंभीर, अनुशासित और आत्मचिंतन से परिपूर्ण काल माना जाता है। भारतीय दर्शन में भगवान विष्णु का योगनिद्रा में जाना किसी निष्क्रियता का प्रतीक नहीं है। यह एक गहरा दार्शनिक संदेश है कि जब सृष्टि के पालनकर्ता स्वयं मौन होकर ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं, तब मनुष्य को भी अपने जीवन की गति धीमी करके स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए। आज का मनुष्य बाहरी उपलब्धियों के पीछे इतना अधिक दौड़ रहा है कि उसे अपने भीतर झांकने का अवसर ही नहीं मिल पाता। यही कारण है कि भौतिक सुख-सुविधाओं के बावजूद मानसिक तनाव, असंतोष और अकेलेपन की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। देवशयनी एकादशी हमें यही सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। जब मन शांत होता है, तभी विचार निर्मल होते हैं और जब विचार निर्मल होते हैं, तभी जीवन में वास्तविक सुख और संतुलन आता है।

पुराणों में वर्णित है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर योगनिद्रा धारण करते हैं। यह दिव्य निद्रा कार्तिक शुक्ल एकादशी तक रहती है, जिसे देवप्रबोधिनी या देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इन चार महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इस अवधि को भारतीय संस्कृति ने केवल धार्मिक मान्यता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे आत्मसंयम, तप, अध्ययन, साधना और सेवा का श्रेष्ठ समय माना। यह वह काल है, जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखता है, अपने व्यवहार को परिष्कृत करता है और ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को और अधिक गहरा बनाता है।

देवशयनी एकादशी का वास्तविक संदेश यह है कि जीवन केवल उत्सव मनाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने के लिए भी है। पूरे वर्ष मनुष्य अपने परिवार, व्यवसाय, समाज और दायित्वों में व्यस्त रहता है। लेकिन यदि वह समय-समय पर अपने विचारों का परीक्षण नहीं करेगा, अपने आचरण का मूल्यांकन नहीं करेगा और अपने भीतर की कमियों को दूर करने का प्रयास नहीं करेगा, तो उसका विकास अधूरा रह जाएगा। इसलिए भारतीय संस्कृति ने चातुर्मास को आत्मशुद्धि का विशेष अवसर माना। यह समय बाहरी भव्यता से अधिक आंतरिक जागरण का समय है।

इस पावन तिथि पर श्रद्धालु प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मंदिरों में विशेष श्रृंगार किया जाता है, तुलसीदल अर्पित किए जाते हैं और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप किया जाता है। अनेक श्रद्धालु निर्जल उपवास रखते हैं, कुछ केवल फलाहार करते हैं और कुछ सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए व्रत का पालन करते हैं। इस दिन विष्णु सहस्रनाम, भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत और रामचरितमानस का पाठ करने की परंपरा है। दान-पुण्य का भी विशेष महत्व माना गया है। अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान और जरूरतमंदों की सहायता को भगवान विष्णु की सच्ची आराधना माना गया है। भारतीय संस्कृति का मूल संदेश भी यही है कि पूजा तभी पूर्ण होती है, जब उसके साथ करुणा और सेवा जुड़ी हो।

देवशयनी एकादशी का सांस्कृतिक महत्व भी अत्यंत व्यापक है। इसी दिन से विवाह, गृहप्रवेश, यज्ञोपवीत, मुंडन और अन्य बड़े मांगलिक कार्यों पर अस्थायी विराम लग जाता है। कई लोग इसे केवल धार्मिक परंपरा मानते हैं, लेकिन इसके पीछे गहरा व्यवहारिक और वैज्ञानिक आधार भी है। वर्षा ऋतु में प्राचीन भारत के अधिकांश मार्ग कच्चे होते थे। यात्राएं कठिन हो जाती थीं, नदियां उफान पर होती थीं और बड़े आयोजन करना सुविधाजनक नहीं होता था। इसलिए समाज ने इस अवधि को बाहरी आयोजनों की अपेक्षा आत्मिक उन्नति और सामुदायिक शिक्षा के लिए निर्धारित किया। यह भारतीय जीवन-दर्शन की अद्भुत दूरदर्शिता का प्रमाण है।

चातुर्मास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष संत परंपरा है। वर्षभर देशभर में भ्रमण करने वाले संत और महात्मा इन चार महीनों तक एक ही स्थान पर निवास करते हैं। वहां प्रतिदिन भागवत कथा, रामकथा, गीता प्रवचन, वेदांत चर्चा, भजन-कीर्तन और धर्मसभा का आयोजन होता है। इन आयोजनों के माध्यम से समाज को केवल धार्मिक ज्ञान ही नहीं मिलता, बल्कि नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। पहले भारत के लगभग प्रत्येक गांव में चातुर्मास के दौरान कोई न कोई संत अवश्य ठहरता था। पूरा गांव प्रतिदिन एकत्र होकर कथा सुनता, बच्चे संस्कार सीखते और युवाओं को जीवन का सही मार्गदर्शन मिलता। यही परंपरा भारतीय समाज की सांस्कृतिक एकता की सबसे मजबूत आधारशिला बनी।

महाराष्ट्र की प्रसिद्ध पंढरपुर वारी देवशयनी एकादशी की सबसे भव्य और प्रेरणादायक परंपराओं में से एक है। लाखों वारकरी सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर भगवान विट्ठल के दर्शन करने पंढरपुर पहुंचते हैं। इस यात्रा में न कोई बड़ा होता है और न कोई छोटा। सभी श्रद्धालु समान भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं। हाथों में भगवा ध्वज, मुख पर अभंग और हृदय में विठोबा के प्रति अटूट प्रेम—यही इस यात्रा की पहचान है। यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि अनुशासन, सेवा, समानता और सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण है।

वारकरी परंपरा संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव और संत एकनाथ जैसे महान संतों की शिक्षाओं पर आधारित है। संत ज्ञानेश्वर की पालखी आलंदी से और संत तुकाराम की पालखी देहू से निकलती है। हजारों श्रद्धालु इन पालखियों के साथ भजन गाते हुए पंढरपुर तक की यात्रा करते हैं। यह यात्रा बताती है कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि विनम्रता, अनुशासन और सेवा में है। वारकरी परंपरा ने सदियों से समाज को जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर समानता और प्रेम का संदेश दिया है।

चातुर्मास भारतीय लोकजीवन और सांस्कृतिक धरोहर का भी सबसे समृद्ध काल है। गांवों और नगरों में रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत, शिवपुराण और देवी भागवत की कथाएं आयोजित होती हैं। लोकभाषाओं में भजन, अभंग, दोहे, चौपाइयां और कीर्तन गाए जाते हैं। इन्हीं आयोजनों ने भारतीय लोकसाहित्य को पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुरक्षित रखा। यही कारण है कि आज भी भारत के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग मिल जाते हैं, जिन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त की, लेकिन उन्हें रामायण, महाभारत और संत साहित्य के अनेक प्रसंग कंठस्थ होते हैं। यह चातुर्मास की सांस्कृतिक परंपरा की ही अमूल्य देन है।

आयुर्वेद के अनुसार भी यह अवधि विशेष महत्व रखती है। वर्षा ऋतु में पाचन शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर हो जाती है और अनेक रोगों की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सात्विक भोजन, उपवास, हल्का आहार और नियमित दिनचर्या अपनाने की सलाह दी जाती है। यह दर्शाता है कि भारतीय धार्मिक परंपराएं केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य विज्ञान पर भी आधारित हैं। उपवास का उद्देश्य केवल धार्मिक नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि शरीर और मन दोनों को संतुलित रखना भी है।

आज का आधुनिक समाज अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति कर चुका है। जीवन सुविधाजनक हुआ है, लेकिन मानसिक शांति पहले की अपेक्षा कम होती जा रही है। तनाव, प्रतिस्पर्धा, उपभोक्तावाद और निरंतर भागदौड़ ने मनुष्य को भीतर से थका दिया है। ऐसे समय में देवशयनी एकादशी का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि सफलता केवल धन और पद प्राप्त करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति, संतोष और करुणा विकसित करने में भी है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

गुजरात में चांदीपुरा वायरस से बढ़ी चिंता, 63 संदिग्ध मामलों में 12 की पुष्टि; बच्चों की सुरक्षा पर सरकार का विशेष फोकस

गांधीनगर। गुजरात में चांदीपुरा वायरस (Chandipura Virus) के बढ़ते मामलों ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। मानसून के बीच बच्चों को प्रभावित करने वाले इस दुर्लभ लेकिन गंभीर वायरस के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने पूरे स्वास्थ्य तंत्र को हाई अलर्ट पर रखा है। संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें वायरस के प्रसार, प्रभावित जिलों की स्थिति, उपचार व्यवस्था और रोकथाम के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं।

स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब तक चांदीपुरा वायरस के 63 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 12 मामलों में संक्रमण की प्रयोगशाला से पुष्टि हो चुकी है। पुष्टि किए गए मामलों में 9 मरीज गुजरात के निवासी हैं, जबकि 3 मरीज राजस्थान के हैं, जिनका उपचार गुजरात के अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कुल संदिग्ध मामलों में से 55 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जबकि 8 नमूनों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। अधिकारियों का कहना है कि नई रिपोर्ट मिलने के बाद स्थिति का दोबारा आकलन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त नियंत्रण उपाय लागू किए जाएंगे।

समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संक्रमण के प्रत्येक मामले की गहराई से जांच की जाए। उन्होंने कहा कि केवल मरीज का उपचार ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि संक्रमण किस प्रकार फैला, मरीज किन क्षेत्रों में गया था, उसके संपर्क में कौन-कौन लोग आए और संक्रमण का संभावित स्रोत क्या हो सकता है। इसके लिए प्रत्येक मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और केस हिस्ट्री का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक सबसे अधिक प्रभावित जिलों में पंचमहल और खेड़ा शामिल हैं, जहां दो-दो पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसके अलावा साबरकांठा, मेहसाणा, भरूच, भावनगर और अहमदाबाद नगर निगम क्षेत्र में एक-एक संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। सरकार ने इन सभी जिलों में विशेष निगरानी अभियान शुरू कर दिया है। जिन इलाकों से संक्रमित मरीज मिले हैं, वहां स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार सर्वेक्षण कर रही हैं और आसपास के परिवारों की भी स्वास्थ्य जांच की जा रही है, ताकि संक्रमण के किसी नए मामले की समय रहते पहचान की जा सके।

चांदीपुरा वायरस के मामलों को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर डोर-टू-डोर हेल्थ स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है। हजारों कच्चे और पक्के मकानों में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। विशेष रूप से छोटे बच्चों की निगरानी की जा रही है, क्योंकि यह वायरस मुख्य रूप से बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी बच्चे में संदिग्ध लक्षण दिखाई देने पर उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल भेजा जाए, ताकि समय रहते उपचार शुरू किया जा सके।

राज्य सरकार ने वायरस के संभावित वाहक सैंडफ्लाई (बालू मक्खी) और अन्य कीटों पर नियंत्रण के लिए भी व्यापक अभियान शुरू किया है। प्रभावित गांवों और बस्तियों में कच्चे मकानों,

पशुओं के बाड़ों और आसपास के क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर कीटनाशक डस्टिंग और छिड़काव कराया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि मानसून के दौरान नमी और अस्वच्छ वातावरण में ऐसे कीटों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका भी बढ़ जाती है। इसलिए केवल मरीजों के उपचार पर ही नहीं, बल्कि संक्रमण फैलाने वाले कारकों को नियंत्रित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने बैठक में स्पष्ट किया कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों के सिविल अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों के लिए आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, जीवनरक्षक दवाओं, ऑक्सीजन सपोर्ट तथा प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यदि किसी जिले में मरीजों की संख्या बढ़ती है तो वहां अतिरिक्त चिकित्सा दल और संसाधन भी भेजे जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि सामान्यतः मानसून के दौरान सितंबर तक चांदीपुरा वायरस की सक्रियता अधिक देखी जाती है। इसी कारण अगले कुछ सप्ताह स्वास्थ्य विभाग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिदिन संक्रमण की स्थिति की रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को भेजें और किसी भी नए मामले की तत्काल सूचना दें। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार चांदीपुरा वायरस एक वायरल संक्रमण है, जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है और कुछ मामलों में यह तेजी से गंभीर रूप ले सकता है। संक्रमित बच्चे में अचानक तेज बुखार, उल्टी, दस्त, सुस्ती, दौरे पड़ना, बेहोशी या मानसिक स्थिति में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर इलाज में देरी करना खतरनाक साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती पहचान और समय पर चिकित्सा सुविधा मिलने से मरीज की स्थिति को बेहतर ढंग से संभाला जा सकता है।

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। छोटे बच्चों को साफ-सुथरे वातावरण में रखें, घर और आसपास सफाई बनाए रखें, बच्चों को कीटों के संपर्क से बचाने के लिए पूरी बांह के कपड़े पहनाएं तथा रात में मच्छरदानी या अन्य सुरक्षा उपायों का उपयोग करें। यदि किसी बच्चे में तेज बुखार, बार-बार उल्टी, दौरे या बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दें तो घरेलू उपचार में समय गंवाने के बजाय तुरंत सरकारी अस्पताल या बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें।

स्वास्थ्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य में निगरानी व्यवस्था लगातार मजबूत की जा रही है। जिला प्रशासन, नगर निकायों, पंचायतों और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लोगों को संक्रमण से बचाव के उपायों, लक्षणों की पहचान और समय पर उपचार के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है।

राज्य सरकार का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन मानसून के मौसम को देखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर संदिग्ध मामले की गंभीरता से जांच की जाए, प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जाए और जरूरत पड़ने पर तत्काल अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। सरकार का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और चांदीपुरा वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम लगातार उठाए जा रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में भरूच के दहेज में 2153 करोड़ रुपए के ड्रग्स का नाश किया गया

- **गुजरात पुलिस ने ड्रग्स माफियाओं और कार्टेल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क की कमर तोड़ दी है : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी**
- **ड्रग्स मुक्त गुजरात के संकल्प को साकार करने के लिए पुलिस के साथ सामाजिक संस्थाएं और नागरिक भी भागीदार बनें : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी**
- **ड्रग्स मामलों में गुजरात पुलिस का कन्विक्शन रेशियो लगभग 65 प्रतिशत, इसे 100 प्रतिशत तक पहुंचाने की दिशा में कार्य जारी; ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े अपराधियों पर कानूनी शिकंजा और अधिक मजबूत किया जाएगा**
- **जांच अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए तैयार की गई 'एनडीपीएस हैंडबुक' का विमोचन**
- **राज्य सरकार की 'रिवॉर्ड पॉलिसी' अंतर्गत ड्रग्स के विरुद्ध उत्कृष्ट कार्य करने वाले 278 पुलिसकर्मियों को 59.42 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित**

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के 'नशा-मुक्त गुजरात' के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी सोमवार को भरूच के दहेज स्थित 'एन्वायरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' द्वारा आयोजित ड्रग्स उन्मूलन कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री तथा ड्रग्स निस्तारण समिति के सदस्यों ने ड्रग्स के जप्त भंडार का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर उसकी जानकारी प्राप्त की। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के 'ड्रग्स-फ्री इंडिया' के आह्वान तथा 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति से इस सभी नारकोटिक्स के भंडार का गैर हानिकारक तरीके से नाश किया गया। इसी स्थल से उप मुख्यमंत्री ने लकडिया (भचाऊ) में आयोजित नार्कोटिक्स कार्यक्रम का भी ऑनलाइन शुभारंभ कराया।

इस कार्यक्रम में राज्य की 24 इकाइयों द्वारा कुल 867 मामलों में जप्त 2153 करोड़ रुपए मूल्य के नारकोटिक्स भंडार (13,249.127 किलोग्राम ड्रग्स तथा 5,71,028 बोतलों) का नाश किया गया। इस कार्रवाई में भरूच, नर्मदा, सूरत ग्रामीण, सूरत शहर, नवसारी, तापी-व्यारा, दाहोद, छोटाउदेपुर, पंचमहल, डांग-आहवा, वलसाड, वडोदरा ग्रामीण, वडोदरा शहर, आणंद, खेडा-नडियाद, पश्चिम रेलवे (वडोदरा एवं अहमदाबाद), अहमदाबाद ग्रामीण, अहमदाबाद शहर, गांधीनगर, मेहसाणा, साबरकांठा सहित सीआईडी क्राइम तथा एटीएस की टीमों का कार्य सम्मिलित की गई। इसके बाद दहेज स्थित जीएसीएल कंपनी में एनडीपीएस हैंडबुक के विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुजरात पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा तैयार की गई इस हैंडबुक का मुख्य उद्देश्य जांच अधिकारियों को सुदृढ़ मार्गदर्शन प्रदान करना तथा कानून का कड़ाई से प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

इसके अतिरिक्त; पुलिस विभाग द्वारा तैयार किए गए 'ड्रग्स मुक्त गुजरात' जागरूकता वीडियो, व्यसनमुक्त हुए पीड़ितों के अनुभवों पर आधारित लघु फिल्म तथा विशेष प्रेजेंटेशन भी प्रदर्शित किया गया।

पुलिस विभाग को बधाई देते हुए उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि वर्तमान समय में समाज की सबसे बड़ी बुराई ड्रग्स है। इस बुराई के विरुद्ध गुजरात पुलिस जिस प्रकार संघर्ष कर रही है, वह वास्तव में सराहनीय है। समुद्र की तेज लहरों के बीच, भारत-पाकिस्तान सीमा पर तथा अन्य राज्यों में फैले अपराधियों के 'मोडस ऑपरेंडी' को ध्वस्त करने में गुजरात पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। गुजरात पुलिस ने ड्रग्स माफियाओं और कार्टेल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। पिछले डेढ़ वर्ष से इस अभियान को युद्ध स्तर पर चलाकर हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए हैं।

उन्होंने जोड़ा कि गुजरात में ड्रग्स से संबंधित मामलों में कन्विक्शन रेशियो लगभग 65 प्रतिशत है, जो कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रमाण है। आने वाले समय में ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े अपराधियों के विरुद्ध ऐसी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी कि उन्हें किसी भी प्रकार की कानूनी राहत या छूट का अवसर न मिल सके।

पुलिस के मानवीय दृष्टिकोण की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रग्स बेचने वालों की गिरफ्तारी के बाद उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर इस बुराई में फंसे युवाओं तथा उनके परिवारों की काउंसलिंग कर उन्हें सही दिशा दिखाने का सराहनीय कार्य भी गुजरात पुलिस द्वारा किया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री ने राज्य के नागरिकों एवं सामाजिक संस्थाओं से अपील करते हुए कहा कि पुलिस की कठोर कार्रवाई के साथ-साथ जब पूरा समाज और नागरिक भी इस लड़ाई में सहभागी बनेंगे, तभी 'ड्रग्स मुक्त गुजरात' का संकल्प पूर्ण रूप से साकार होगा।

राज्य सरकार की 'ड्रग्स रिवॉर्ड पॉलिसी' अंतर्गत विभिन्न 21 बड़े मामलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 278 पुलिसकर्मियों को 59.42 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया गया।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती डिम्पलबेन राज, विधायक सर्वश्री अरुणसिंह राणा, रमेश मिस्त्री, रीतेश वसावा, डी. के. स्वामी, राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री जी. एस. मलिक, सीआईडी क्राइम के महानिदेशक डॉ. के. एल. राव, वडोदरा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री संदीप सिंह, सीआईडी क्राइम के पुलिस महानिरीक्षक श्री गौतम परमार, जिला कलेक्टर डॉ. नवनाथ गव्हाणे, जिला विकास अधिकारी श्री योगेश कापसे सहित पुलिस विभाग, प्रशासनिक तंत्र तथा जीएसीएल कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

ट्राई की नेटवर्क जांच में जियो सबसे आगे, एयरटेल ने भी दिखाई मजबूती; बीएसएनएल और वीआई कई इलाकों में रहे पीछे

नई दिल्ली। देश में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता को लेकर दूरसंचार नियामक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा किए गए ताजा परीक्षण में निजी दूरसंचार कंपनियों रिलायंस जियो और भारती एयरटेल का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। वहीं सरकारी कंपनी बीएसएनएल और निजी ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया (वीआई) कई क्षेत्रों में नेटवर्क गुणवत्ता, डेटा स्पीड और कॉल ड्रॉप के मामले में अपेक्षाकृत कमजोर साबित हुए हैं। ट्राई ने मई और जून के दौरान हिमाचल प्रदेश तथा मध्यप्रदेश के विभिन्न शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यापक नेटवर्क गुणवत्ता परीक्षण (ड्राइव टेस्ट) किया, जिसमें मोबाइल इंटरनेट की गति, कॉल ड्रॉप, कॉल सेटअप सफलता और नेटवर्क की स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण मानकों का मूल्यांकन किया गया।

संचार मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार यह परीक्षण वास्तविक परिस्थितियों में किया गया, ताकि उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाओं का सही आकलन किया जा सके। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर-बिलासपुर क्षेत्र और मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर-नीमच हाईवे तथा बिलासपुर-अंबिकापुर हाईवे पर चारों प्रमुख दूरसंचार कंपनियों—रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल—के नेटवर्क का तुलनात्मक परीक्षण किया गया।

सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शन रिलायंस जियो का रहा, जिसने लगभग सभी स्थानों पर डाउनलोड स्पीड और कॉल गुणवत्ता के मामले में अन्य कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। ट्राई के आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में जियो ने औसत 291.53 एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड दर्ज की, जो सभी कंपनियों में सबसे अधिक रही। इसके मुकाबले एयरटेल की औसत डाउनलोड स्पीड 44.25 एमबीपीएस, वीआई की 63.96 एमबीपीएस और बीएसएनएल की केवल 10.68 एमबीपीएस रही।

भोपाल में केवल डेटा स्पीड ही नहीं, बल्कि कॉल गुणवत्ता के मामले में भी जियो का प्रदर्शन बेहतर रहा। परीक्षण के दौरान जियो और वीआई के केवल एक-एक कॉल असफल रहे, जबकि एयरटेल के तीन और बीएसएनएल के 16 कॉल सफलतापूर्वक स्थापित नहीं हो सके। इससे स्पष्ट होता है कि बीएसएनएल को नेटवर्क स्थिरता और कॉल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभी काफी सुधार की आवश्यकता है।

इंदौर-नीमच राष्ट्रीय राजमार्ग पर किए गए परीक्षण में भी जियो ने अपना दबदबा कायम रखा। यहां उसकी औसत डाउनलोड स्पीड 216.50 एमबीपीएस दर्ज की गई। एयरटेल ने 86.90 एमबीपीएस की गति के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि वीआई की औसत स्पीड 21.44 एमबीपीएस और बीएसएनएल की 9.13 एमबीपीएस रही। इस मार्ग पर कॉल गुणवत्ता के मामले में भी जियो का प्रदर्शन सबसे प्रभावशाली रहा। परीक्षण के दौरान जियो के नेटवर्क पर एक भी कॉल ड्रॉप दर्ज नहीं हुई, जबकि अन्य कंपनियों के नेटवर्क पर कुछ कॉल ड्रॉप और कॉल असफलता के मामले सामने आए। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी दूरी के राजमार्गों पर निर्बाध नेटवर्क उपलब्ध कराना तकनीकी दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है और ऐसे क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बिलासपुर-अंबिकापुर हाईवे पर भी जियो ने सबसे अधिक 150.95 एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड दर्ज की। एयरटेल की औसत स्पीड 40.32 एमबीपीएस, वीआई की 17.99 एमबीपीएस और बीएसएनएल की 10.76 एमबीपीएस रही। कॉल ड्रॉप के मामले में भी जियो अन्य कंपनियों की तुलना में बेहतर स्थिति में रहा। यहां जियो के दो, एयरटेल के चार, वीआई के छह और बीएसएनएल के 14 कॉल ड्रॉप दर्ज किए गए। इससे स्पष्ट है कि नेटवर्क स्थिरता के मामले में बीएसएनएल को सबसे अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्राई ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर-बिलासपुर मार्ग पर भी नेटवर्क गुणवत्ता की जांच की। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां नेटवर्क उपलब्ध कराना अपेक्षाकृत कठिन माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद जियो और एयरटेल ने संतोषजनक प्रदर्शन किया। परीक्षण में जियो की औसत डाउनलोड स्पीड 243.12 एमबीपीएस दर्ज की गई, जबकि एयरटेल ने 171.15 एमबीपीएस की गति हासिल की। इसके विपरीत बीएसएनएल की औसत डाउनलोड स्पीड 11.29 एमबीपीएस और वीआई की 13.51 एमबीपीएस रही। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्राई के ड्राइव टेस्ट केवल इंटरनेट स्पीड मापने तक सीमित नहीं होते, बल्कि इनके माध्यम से कॉल कनेक्टिविटी, नेटवर्क कवरेज, कॉल सेटअप सफलता दर, वॉइस गुणवत्ता और नेटवर्क की निरंतर उपलब्धता जैसे कई तकनीकी मानकों का मूल्यांकन किया जाता है। इन परीक्षणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि दूरसंचार कंपनियां अपने लाइसेंस की शर्तों और निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन कर रही हैं या नहीं।

बुनियादी क्षेत्रों में उत्पादन ने पकड़ी रफ्तार, जून में पांच महीने की सबसे तेज 5% वृद्धि; निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों को मिला नया बल

नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जून 2026 से उत्साहजनक संकेत सामने आए हैं। देश के नौ प्रमुख बुनियादी (कोर) क्षेत्रों के उत्पादन में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले पांच महीनों का सबसे मजबूत प्रदर्शन माना जा रहा है। इस तेजी से यह संकेत मिल रहे हैं कि निर्माण, बुनियादी ढांचा और औद्योगिक गतिविधियां धीरे-धीरे गति पकड़ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कोर सेक्टर में आई यह मजबूती आने वाले महीनों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी), निवेश गतिविधियों और समग्र आर्थिक विकास को भी सकारात्मक समर्थन दे सकती है।

सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मई 2026 में कोर सेक्टर की वृद्धि दर 3.2 प्रतिशत थी, जबकि जून 2025 में यह केवल 1.1 प्रतिशत दर्ज की गई थी। ऐसे में जून 2026 के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि प्रमुख बुनियादी क्षेत्रों में उत्पादन गतिविधियां उल्लेखनीय रूप से तेज हुई हैं। कोर सेक्टर का प्रदर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों का सीधा प्रभाव देश के औद्योगिक उत्पादन और आर्थिक विकास पर पड़ता है।

इस बार सरकार ने कोर सेक्टर के आंकड़े नए आधार वर्ष 2022-23 के अनुसार जारी किए हैं। इससे पहले इनकी गणना का आधार वर्ष 2011-12 था। नए आधार वर्ष के साथ आंकड़ों की संरचना में भी बदलाव किया गया है। अब लौह अयस्क (Iron Ore) को भी कोर सेक्टर में शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद प्रमुख बुनियादी क्षेत्रों की संख्या आठ से बढ़कर नौ हो गई है। सरकार का मानना है कि नए आधार वर्ष और संशोधित संरचना से देश की वर्तमान औद्योगिक स्थिति का अधिक सटीक आकलन संभव होगा।

जून 2026 के दौरान सबसे उल्लेखनीय वृद्धि लौह अयस्क उत्पादन में दर्ज की गई, जिसमें 43.9 प्रतिशत का उछाल आया। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बढ़ोतरी से इस्पात उद्योग और निर्माण क्षेत्र की बढ़ती मांग का संकेत मिलता है। बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का उत्पादन इस बात का भी संकेत है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आ रही है।

इसी प्रकार सीमेंट उत्पादन और बिजली उत्पादन में भी 9.8-9.8 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। सीमेंट उत्पादन में तेजी को निर्माण क्षेत्र की सक्रियता का प्रमुख संकेत माना जाता है। देशभर में सड़क, रेलवे, आवास, औद्योगिक परियोजनाओं और सार्वजनिक अवसंरचना के विकास में तेजी के कारण सीमेंट की मांग बढ़ रही है। वहीं बिजली उत्पादन में वृद्धि से यह स्पष्ट होता है कि उद्योगों और व्यावसायिक गतिविधियों में ऊर्जा की खपत बढ़ी है, जो आर्थिक गतिविधियों के विस्तार का संकेत देती है।

हालांकि सभी क्षेत्रों का प्रदर्शन समान रूप से सकारात्मक नहीं रहा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद तथा उर्वरक क्षेत्रों में उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। ऊर्जा क्षेत्र के इन हिस्सों में आई कमजोरी को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि उत्पादन संबंधी चुनौतियां, रखरखाव कार्य, वैश्विक बाजार की परिस्थितियां तथा मांग-आपूर्ति से जुड़े कारक इसके पीछे जिम्मेदार हो सकते हैं। इसके बावजूद निर्माण और अवसंरचना क्षेत्र की मजबूत वृद्धि ने समग्र कोर सेक्टर के प्रदर्शन को सकारात्मक बनाए रखा।

आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि कोर सेक्टर में आई तेजी विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन क्षेत्रों का योगदान देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में लगभग 40 प्रतिशत होता है। इसलिए कोर सेक्टर के मजबूत आंकड़े आने वाले महीनों में औद्योगिक उत्पादन के बेहतर रहने का संकेत भी माने जा रहे हैं। यदि यह रुझान जारी रहता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव विनिर्माण, रोजगार और निवेश गतिविधियों पर भी दिखाई दे सकता है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) के दौरान नौ प्रमुख बुनियादी क्षेत्रों की औसत उत्पादन वृद्धि 3.6 प्रतिशत रही। इसके मुकाबले पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह वृद्धि केवल 1 प्रतिशत थी।

नेपाल से शुल्क-मुक्त खाद्य तेल आयात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, घरेलू उद्योग ने जताई चिंता; सरकार से नियमों की समीक्षा की मांग

नई दिल्ली। नेपाल से भारत में आने वाले शुल्क-मुक्त रिफाइंड खाद्य तेल के आयात में पिछले दो वर्षों के दौरान हुई अभूतपूर्व वृद्धि ने देश के वनस्पति तेल उद्योग की चिंता बढ़ा दी है। भारतीय वनस्पति तेल उत्पादक संघ (आईवीपीए) ने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले की व्यापक समीक्षा करने और घरेलू रिफाइनिंग उद्योग, तिलहन किसानों तथा सरकारी राजस्व पर पड़ रहे संभावित प्रभावों का आकलन कर आवश्यक नीतिगत कदम उठाने की मांग की है। उद्योग संगठन का कहना है कि यदि वर्तमान स्थिति जारी रही तो देश के रिफाइनिंग उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हो सकती है, घरेलू तिलहन उत्पादन प्रभावित हो सकता है और सरकार को सीमा शुल्क के रूप में हजारों करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ सकता है।

आईवीपीए के अनुसार, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) समझौते के तहत नेपाल से भारत में शुल्क-मुक्त खाद्य तेल आयात की व्यवस्था का लाभ उठाते हुए आयात में असाधारण वृद्धि दर्ज की गई है। संगठन के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023 में नेपाल से 47,295 टन रिफाइंड खाद्य तेल का आयात हुआ था, जबकि 2025 में यह बढ़कर 8.04 लाख टन से अधिक पहुंच गया। यानी केवल दो वर्षों में आयात लगभग 17 गुना बढ़ गया है। उद्योग संगठन का अनुमान है कि यदि यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले समय में नेपाल से खाद्य तेल आयात 10 लाख टन प्रतिवर्ष के

स्तर को भी पार कर सकता है।

आईवीपीए के अध्यक्ष सुधाकर देसाई ने कहा कि भारत हमेशा क्षेत्रीय व्यापार सहयोग और पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का समर्थक रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी व्यापार व्यवस्था का उद्देश्य घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाना नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार शुल्क-मुक्त आयात की मौजूदा स्थिति का प्रभाव भारतीय रिफाइनिंग उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। इसलिए समय रहते सरकार को इस व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि घरेलू उद्योग और किसानों के हित सुरक्षित रह सकें।

संगठन का कहना है कि भारत ने पिछले कई वर्षों में खाद्य तेल रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है। देश में आधुनिक रिफाइनरियां स्थापित की गई हैं और हजारों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। यदि बड़ी मात्रा में तैयार रिफाइंड खाद्य तेल शुल्क-मुक्त आयात होता रहेगा, तो घरेलू रिफाइनरियों की उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा। इससे नए निवेश प्रभावित हो सकते हैं और उद्योग की दीर्घकालिक विकास योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है।

आईवीपीए ने यह भी आशंका व्यक्त की है कि आयात में लगातार बढ़ोतरी का प्रभाव केवल उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर किसानों पर भी पड़ेगा। भारत में सोयाबीन, सरसों और अन्य तिलहनों की खेती करने वाले लाखों किसान घरेलू मांग पर निर्भर हैं। यदि आयातित रिफाइंड तेल बड़ी मात्रा में कम लागत पर बाजार में उपलब्ध रहेगा, तो घरेलू तिलहनों की मांग कमजोर हो सकती है। इसका सीधा प्रभाव किसानों को मिलने वाले मूल्य और उनकी आय पर पड़ने की आशंका है।

संगठन ने सरकार के समक्ष एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उसके अनुसार नेपाल से शुल्क-मुक्त आयात में तेज वृद्धि के कारण केंद्र सरकार को सीमा शुल्क के रूप में मिलने वाले राजस्व में भी बड़ी कमी आ सकती है। आईवीपीए का अनुमान है कि वर्तमान स्थिति के कारण सरकार को प्रति वर्ष लगभग 2,000 से 2,500 करोड़ रुपये तक के सीमा शुल्क राजस्व का नुकसान हो सकता है। उद्योग संगठन का मानना है कि इस वित्तीय प्रभाव का भी गंभीरता से अध्ययन किया जाना चाहिए।

आईवीपीए ने स्पष्ट किया है कि उसका उद्देश्य नेपाल के साथ वैध और नियमसम्मत व्यापार का विरोध करना नहीं है। संगठन का कहना है कि भारत और नेपाल के बीच आर्थिक संबंध दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं और उन्हें आगे भी मजबूत होना चाहिए। हालांकि उसने यह मांग जरूर की है कि साफ्टा (SAFTA) समझौते के तहत मिलने वाली शुल्क छूट केवल उन्हीं उत्पादों को मिले, जो वास्तव में 'मूल स्थान के नियम' (Rules of Origin) का पालन करते हों। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शुल्क लाभ केवल उन्हीं वस्तुओं को मिले, जिनका वास्तविक उत्पादन संबंधित सदस्य देश में हुआ हो।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी तीसरे देश से आयातित कच्चे माल को केवल सीमित प्रसंस्करण के बाद नेपाल से भारत भेजा जाता है, तो ऐसे मामलों की भी नियमों के अनुरूप जांच आवश्यक है। हालांकि इस संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता का आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। उद्योग संगठन केवल मौजूदा आयात प्रवृत्ति की समीक्षा और नियमों के प्रभावी अनुपालन की मांग कर रहा है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक देश है। घरेलू उत्पादन देश की कुल आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए भारत को पाम ऑयल, सोया ऑयल और सूरजमुखी तेल सहित विभिन्न खाद्य तेलों का बड़े पैमाने पर आयात करना पड़ता है। सरकार भी लंबे समय से तिलहन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। ऐसे में उद्योग का मानना है कि आयात नीति और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की रणनीति के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि घरेलू रिफाइनिंग उद्योग को पर्याप्त संरक्षण और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण नहीं मिला, तो भविष्य में इस क्षेत्र में निवेश की गति धीमी पड़ सकती है। दूसरी ओर उपभोक्ताओं के हितों को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि खाद्य तेल की उपलब्धता और कीमतें देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय हैं।

अब उद्योग की निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी हैं। यदि सरकार इस मामले की समीक्षा करती है तो साफ्टा समझौते के तहत आयात व्यवस्था, मूल स्थान के नियमों के अनुपालन और घरेलू उद्योग पर पड़ रहे प्रभाव का विस्तृत मूल्यांकन किया जा सकता है। इससे एक ऐसी नीति तैयार करने की संभावना बनेगी, जिसमें क्षेत्रीय व्यापार सहयोग भी बना रहे और भारतीय उद्योग, किसानों तथा सरकारी राजस्व के हितों का भी संतुलित संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

विश्व धरोहरों को भव्य-दिव्य बनाने में जुटी गुजरात सरकार

पावागढ़ पर 'विकास पताका' : 359 करोड़ रुपए के मेगा मास्टर प्लान से महाकाली धाम में आधुनिक सुविधाओं के निर्माण की धूम

- दो चरणों में 121 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर व परिसर में नवीनीकरण-विस्तारीकरण सहित विकास कार्यों की झड़ी
- 545 वर्ग मीटर से लगभग 6 गुना बढ़कर 2980 वर्ग मीटर विशाल हुआ मंदिर परिसर
- माँची से मंदिर तक 2374 सीढ़ियों का निर्माण तथा पाथ-वे बना और अधिक सुविधाजनक
- तीसरे चरण में 148 करोड़ रुपए से माँची से मंदिर परिसर, चाँपानेर तथा वडा तालाब के विकास कार्यों का आयोजन
- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री का 'विकास भी, विरासत भी' मंत्र हो रहा है साकार

गांधीनगर : गुजरात सहित देश-दुनिया के पर्यटकों एवं माईभक्त श्रद्धालुओं के लिए यात्राधाम 'महाकाली मंदिर-पावागढ़' एक महत्वपूर्ण हॉट फेवरेट हेरिटेज-रिलीजियन टूरिज्म स्पॉट है। पावागढ़ प्राचीन-पुरातन काल से माईभक्तों के लिए श्रद्धा एवं आस्था का केन्द्र रहा है। इतना ही नहीं; पावागढ़-महाकाली मंदिर सहित समग्र चाँपानेर आर्कियोलॉजी पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार जब राज्य की सभी विश्व धरोहरों के संरक्षण तथा विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तब पावागढ़-चाँपानेर में भी विकास तथा सुविधाओं के लगातार विस्तार की धूम है।

गुजरात सरकार फहरा रही पावागढ़ पर 'विकास पताका'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार करोड़ों हिन्दुओं व माईभक्तों की आस्था के इस विश्व प्रसिद्ध केन्द्र पर विकास की पताका फहरा रही है। राज्य सरकार ने पावागढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए 359 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले मेगा मास्टर प्लान के साथ यहाँ विकास कार्यों तथा ढाँचागत सुविधाओं की झड़ी लगा दी है। चार चरणों वाले मास्टर प्लान अंतर्गत पावागढ़ में बड़े पैमाने पर यात्री सुविधाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास कार्य चल रहे हैं, जिनमें पहले तथा दूसरे चरण के कार्य पूरे हो गए हैं।

दो चरणों में श्रद्धालुओं को मिली 121 करोड़ रुपए की सुविधाएँ

गुजरात सरकार तथा उसके उपक्रम गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड द्वारा इस मेगा मास्टर प्लान अंतर्गत पावागढ़ में दो चरणों में 121 करोड़ रुपए की लागत से श्रद्धालुओं को सुविधाओं की बड़ी भेंट दी गई है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मंदिर तथा मंदिर परिसर का नवीनीकरण तथा विस्तारीकरण। पहले मंदिर परिसर 545 वर्ग मीटर का था, जो अब लगभग 6 गुना बढ़कर तीन लेवल में 2980 वर्ग मीटर का विशाल हो गया है। साथ ही; परिसर में पाथ-वे पर बिजलीकरण, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा; माँची चौक से मंदिर परिसर तक सीढ़ियों के नवीनीकरण-विस्तारीकरण अंतर्गत 3.01 किलोमीटर चौड़े पाथ-वे के साथ कुल 2374 सीढ़ियों का निर्माण किया गया है।

तीसरे-चौथे चरण में और वैभवशाली बनेगा महाकाली धाम

पावागढ़ के महाकाली धाम को तीसरा चरण तथा चौथा चरण और वैभवशाली बनाएंगे, जिनकी कुल लागत 238 करोड़ रुपए है। इसमें 148 करोड़ रुपए की लागत वाले तीसरे चरण को 'फेज-3ए' तथा 'फेज-3बी' में बाँटा गया है। 13.68 करोड़ रुपए की लागत वाले फेज3-ए में माँची चौक में मल्टी-लेवल पार्किंग का कार्य पूरा हो गया है। इसी प्रकार; फेज-3बी में 135.19 करोड़ रुपए की लागत से चाँपानेर में आंतरिक-बाह्य सड़कें, पाथ-वे, इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लांटेशन, 600 से अधिक स्कूटर-कार के लिए विशाल पार्किंग सुविधा, बस सुविधा और इसके अलावा; वडा तालाब परिक्षेत्र में उद्यान, घाट, वाटर जेटी, फुटओवर ब्रिज, थीम पार्क, चिल्ड्रन प्ले एरिया, एक्टिविटी एरिया, बर्ड वॉच टावर, क्राफ्ट स्टॉल और 500 कार पार्किंग सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं।

'विरासत भी, विकास भी' के लिए निरंतर प्रयासरत मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

इस प्रकार; जहाँ एक ओर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात सहित समग्र देश में भारत की प्राचीन संस्कृति, विरासत और पहचान के पुनर्जागरण के लिए 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र के साथ कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी भी हर छोटे-बड़े यात्राधाम-तीर्थधाम तथा आस्थास्थल को उसके प्राचीन-पुरातनकालीन इतिहास के साथ जोड़ने तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ-साथ यात्राधामों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्ज बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

'पावागढ़ पुनरुद्धार' के चार वर्ष, श्रद्धालुओं की संख्या दुगुनी होकर 3.84 करोड़ के पार

इस बीच गत 18 जून, 2026 को 'पावागढ़ पुनरुद्धार' के चार वर्ष पूर्ण हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 जून, 2022 को पावागढ़ के नवनिर्मित शिखर पर 500 वर्षों के बाद कलश तथा ध्वजारोहण किया था। पावागढ़ पुनरुत्थान के बाद यहाँ आने वाले माईभक्तों, श्रद्धालुओं और धार्मिक पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। पावागढ़ पुनरुत्थान के बाद यानी वर्ष 2022-23 से 2025-26 (18 जन, 2026 तक) यानी चार वर्षों में 3 करोड़ 84 लाख से अधिक श्रद्धालु पावागढ़ की यात्रा पर पहुँचे। इससे पहले 2016-17 से 2021-22 तक पाँच वर्ष में 2.32 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावागढ़ की यात्रा की थी। कुल मिलाकर 2016-17 से 2025-26 तक 6.17 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकाली मंदिर के दर्शन को पहुँचे। 2016-17 में जहाँ केवल 38.67 लाख श्रद्धालु पहुँचे थे, वहीं 2025-26 में यह आँकड़ा छह गुना बढ़कर 6. करोड़ 17 लाख से अधिक पर पहुँच गया। ऐसे में पावागढ़ में सरकार द्वारा मेगा मास्टर प्लान अंतर्गत किए जा रहे अनेक विकास-सुविधा कार्यों से श्रद्धालुओं की सुविधा और संख्या में और वृद्धि होगी।

वडोदरा मंडल ने माल लदान में दर्ज की उल्लेखनीय वृद्धि,नई गंतव्य लोडिंग में भी हासिल की बड़ी सफलता

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल ने माल परिवहन के क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए लगातार वृद्धि दर्ज की है। मंडल द्वारा अप्रैल 2026 में 0.98 मिलियन टन, मई 2026 में 1.14 मिलियन टन तथा जून 2026 में 1.27 मिलियन टन माल का लदान किया गया, जो मंडल की बेहतर परिचालन क्षमता एवं ग्राहकों के बढ़ते विश्वास का परिचायक है।मंडल द्वारा अप्रैल - जून 2026 में 3.39 मिलियन टन माल का लदान किया गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के लदान से 4.6 प्रतिशत अधिक है।

जून 2025 की तुलना में जून 2026 के दौरान प्रमुख माल वस्तुओं के लदान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। पेट्रोलियम, ऑयल एवं लुब्रिकेंट्स (POL) का लदान 160 रेक से बढ़कर 247 रेक, कोयले का लदान 97 रेक से बढ़कर 140 रेक, उर्वरक का लदान 78 रेक से बढ़कर 124 रेक तथा कंटेनर लदान 148 रेक से बढ़कर 218 रेक हो गया। यह वृद्धि मंडल की माल परिवहन सेवाओं की बढ़ती दक्षता तथा ग्राहकों द्वारा रेलवे पर बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

इसी क्रम में वडोदरा मंडल ने 17 जुलाई, 2026 को माल ढुलाई के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए DFCCIL's Gati Shakti Multi-Modal Cargo Terminal at New Gothangam (DGGN) से Emirates Terminals Private Limited (EGLY), मध्य रेलवे के लिए 46 बीओबीएसटी (BOBST) वैगनों की नई गंतव्य (New Destination) लोडिंग सफलतापूर्वक प्रारंभ की। इस रेक के माध्यम से एचआर कॉयल (HR Coil) का परिवहन किया गया। यह रेक 388.03 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तथा इससे रेलवे को लगभग 28 लाख का मालभाड़ा राजस्व प्राप्त होने की अपेक्षा है।

नई गंतव्य लोडिंग की यह उपलब्धि वडोदरा मंडल द्वारा नए यातायात स्रोत विकसित करने, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाओं का विस्तार करने तथा माल व्यवसाय को बढ़ावा देने की दिशा में किए जा रहे निरंतर प्रयासों का परिणाम है।

वडोदरा मंडल परिचालन दक्षता, आधुनिक अवसंरचना, ग्राहक-केंद्रित सेवाओं तथा नवाचारों के माध्यम से माल परिवहन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंडल का यह उत्कृष्ट प्रदर्शन पश्चिम रेलवे के माल राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ-साथ भारतीय रेल की आर्थिक प्रगति को भी नई गति प्रदान कर रहा है।

सूरत में क्रीक बाढ़ से स्थायी राहत की तैयारी, पहली बार LiDAR तकनीक से बनेगा वैज्ञानिक मास्टर प्लान; अत्याधुनिक सर्वे के आधार पर तैयार होगी डीपीआर

सूरत। हर वर्ष मानसून के दौरान क्रीक (खाड़ी) क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ से जूझ रहे सूरत के लिए अब एक दीर्घकालिक और वैज्ञानिक समाधान तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने क्रीक बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के उद्देश्य से व्यापक मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी कड़ी में सोमवार को तापी भवन में गठित खाड़ी बाढ़ रोकथाम समिति की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें परियोजना की रूपरेखा, विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां और आधुनिक तकनीक के उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पहली बार पूरे क्रीक क्षेत्र का LiDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) सर्वे कराने का फैसला लिया गया है। इस अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से तैयार होने वाले सटीक त्रि-आयामी डिजिटल मानचित्र के आधार पर बाढ़ नियंत्रण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी।

बैठक में नगर आयुक्त एम. नागराजन, जिला कलेक्टर तेजस परमार, जिला विकास अधिकारी देवेंद्र मीणा, सूरत शहरी विकास प्राधिकरण (सूडा), सिंचाई विभाग, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) तथा विभिन्न तकनीकी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने पिछले वर्षों में आई बाढ़ की परिस्थितियों, क्रीकों की मौजूदा स्थिति, जल निकासी व्यवस्था और भविष्य की आवश्यकताओं की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि केवल अस्थायी उपायों से समस्या का समाधान संभव नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक अध्ययन और आधुनिक तकनीक के आधार पर स्थायी योजना तैयार करनी होगी।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित क्रीक बाढ़ रोकथाम मास्टर प्लान के तहत सबसे पहले पूरे प्रभावित क्षेत्र का विस्तृत सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार होगी, जिसमें क्रीकों की सफाई, चौड़ीकरण, गहराई बढ़ाने, प्राकृतिक जल प्रवाह को बहाल करने, अतिक्रमण की पहचान, जल निकासी नेटवर्क को मजबूत करने तथा भविष्य की शहरी विकास योजनाओं को शामिल किया जाएगा।

बैठक में परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागवार जिम्मेदारियां भी तय कर दी गईं। निर्णय के अनुसार सिंचाई विभाग इस पूरी परियोजना की समन्वय (कोऑर्डिनेटिंग) एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। वहीं जिला भूमि अभिलेख विभाग (डीआईएलआर) को सभी क्रीकों का विस्तृत सर्वेक्षण, मापन और सीमांकन (डिमार्केशन) करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सर्वे और डीपीआर तैयार होने के बाद योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने का कार्य सूरत नगर निगम करेगा।

बैठक के बाद नगर आयुक्त एम. नागराजन ने बताया कि इस बार बाढ़ नियंत्रण योजना पारंपरिक सर्वेक्षण पद्धतियों तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि पहले जहां केवल ड्रोन फोटोग्राफी के आधार पर सीमित जानकारी मिलती थी, वहीं अब पहली बार पूरे क्रीक नेटवर्क का LiDAR सर्वे कराया जाएगा। यह तकनीक क्रीकों की वास्तविक भौगोलिक स्थिति, गहराई, चौड़ाई और प्राकृतिक जल प्रवाह का अत्यंत सटीक डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराएगी।

नगर आयुक्त ने बताया कि LiDAR तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह घने पेड़ों और वनस्पतियों से ढके क्षेत्रों के नीचे की वास्तविक भूमि संरचना का भी सटीक आकलन कर सकती है। सामान्य ड्रोन कैमरे जहां केवल सतह की तस्वीरें उपलब्ध कराते हैं, वहीं LiDAR लेजर तकनीक के माध्यम से पेड़ों के नीचे की वास्तविक जमीन, ढलान, जलमार्ग और अवरोधों की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इससे उन स्थानों की पहचान आसान होगी जहां जल निकासी बाधित होती है या जहां क्रीकों का प्राकृतिक स्वरूप बदल चुका है।

अधिकारियों के अनुसार, सूरत में तेजी से हुए शहरी विस्तार, क्रीकों के किनारे बढ़ते निर्माण कार्य और प्राकृतिक जल निकासी मार्गों में आए बदलाव के कारण मानसून के दौरान कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती रही है। विशेष रूप से तेज बारिश और ऊंचे ज्वार (हाई टाइड) के समय क्रीकों का पानी शहर के निचले इलाकों में भर जाता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नई परियोजना का उद्देश्य इन सभी कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर दीर्घकालिक समाधान तैयार करना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि LiDAR सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर क्रीकों की वास्तविक क्षमता, जल प्रवाह की दिशा, गाद (सिल्ट) जमा होने वाले स्थान, प्राकृतिक ढलान और संभावित अवरोधों का अत्यंत सटीक अध्ययन किया जा सकेगा। इससे भविष्य में बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाएं अधिक प्रभावी और टिकाऊ साबित होंगी। साथ ही शहर के विकास की नई योजनाओं में भी इन आंकड़ों का उपयोग किया जा सकेगा।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सर्वे के दौरान प्राप्त सभी आंकड़ों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संग्रहित किया जाएगा, ताकि भविष्य में विभिन्न विभागों द्वारा एक ही वैज्ञानिक डेटा का उपयोग किया जा सके। इससे नगर नियोजन, सड़क निर्माण, जल निकासी परियोजनाओं, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी बेहतर समन्वय स्थापित होगा।

LiDAR (Light Detection and Ranging) आधुनिक लेजर आधारित सर्वेक्षण तकनीक है, जिसे दुनिया भर में बड़े आधारभूत ढांचा परियोजनाओं, नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, वन क्षेत्र के अध्ययन और शहरी नियोजन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में ड्रोन, हेलीकॉप्टर या विमान से जमीन की ओर प्रति सेकंड हजारों लेजर किरणें भेजी जाती हैं। ये किरणें जमीन, पेड़ों, इमारतों और अन्य संरचनाओं से टकराकर वापस लौटती हैं। लौटने में लगे समय और दूरी के आधार पर अत्यंत सटीक त्रि-आयामी (3D) डिजिटल मॉडल तैयार किया जाता है।

विशेषज्ञों के अनुसार LiDAR तकनीक के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं। इससे क्रीकों और भूमि की वास्तविक ऊंचाई-गहराई का सटीक आकलन किया जा सकता है। घने पेड़ों और झाड़ियों के नीचे की भूमि संरचना भी स्पष्ट रूप से सामने आती है। प्राकृतिक जल प्रवाह, अवरोधों, ढलानों और गाद जमाव का वैज्ञानिक विश्लेषण संभव होता है। यही नहीं, नदी और क्रीक विकास, पुल निर्माण, सड़क परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण योजनाओं और अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए भी यह अत्यंत विश्वसनीय डेटा उपलब्ध कराती है। सामान्य ड्रोन फोटोग्राफी की तुलना में यह तकनीक कहीं अधिक सटीक और वैज्ञानिक परिणाम देती है।

राज्य सरकार का मानना है कि वर्षों से चली आ रही क्रीक बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए यह पहली व्यापक वैज्ञानिक पहल है। यदि परियोजना सफल रहती है तो भविष्य में गुजरात के अन्य तटीय और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी इसी मॉडल को अपनाया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि सर्वे पूरा होने के बाद तैयार होने वाली डीपीआर केवल वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाएगी, बल्कि आने वाले वर्षों में संभावित शहरी विस्तार, जलवायु परिवर्तन और वर्षा के बदलते पैटर्न को भी उसमें शामिल किया जाएगा। प्रशासन को उम्मीद है कि अत्याधुनिक LiDAR तकनीक पर आधारित यह मास्टर प्लान सूरत को हर वर्ष आने वाली क्रीक बाढ़ की समस्या से स्थायी राहत दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके साथ ही शहर में सुरक्षित, वैज्ञानिक और टिकाऊ शहरी विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा, जिससे लाखों नागरिकों को मानसून के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत मिल सकेगी।

सरकारी नौकरियों में 50 बार असफल होने के बाद स्वर्ण पदक विजेता बी.टेक युवक ने आत्महत्या कर ली

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

"माफ़ कीजिए पिताजी, मैंने सरकारी नौकरी पाने के लिए 50 बार कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा, अब मैं ज़िंदगी को अलविदा कह रहा हूँ।" ये शब्द आनंद के सुसाइड नोट में लिखे हैं, जो बिहार के बक्सर निवासी और लोहिया प्राइवेट लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारी राजकुमार के होनहार बेटे थे। आनंद, जो मृत्यु के प्रिय थे, ने 2024 में कानपुर के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक की डिग्री हासिल की थी। राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर उन्हें 13 अगस्त, 2024 को कॉलेज के एक समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। डिग्री पूरी करने के बाद, आनंद निजी क्षेत्र में काम कर रहे थे और सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि बार-बार कोशिश करने के बावजूद, परीक्षा में पास न होने के कारण वे लगातार मानसिक तनाव में थे।

यह घटना कानपुर के गुजेनी स्थित एक किराए के मकान में घटी, जब आनंद के पिता और दादा उसके बड़े भाई (मृत आनंद) के भाई की शादी तय करने बिहार गए हुए थे। आनंद घर पर अकेला था। इस घटना के संबंध में गोविंद नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ अशोक कुमार दुबे ने बताया कि घटनास्थल से पांच पंक्तियों का एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें "सॉरी" शब्द सात से आठ बार लिखा गया है। पुलिस का मानना है कि सरकारी नौकरी न मिलने के कारण अवसाद से ग्रस्त होकर आनंद ने आत्महत्या की है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। इससे सरकार के खोखले दावों की सच्चाई साफ झलकती है, आज देश की स्थिति क्या है?

जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने के बाद मीडिया रिपोर्टों पर सवाल उठने लगे हैं

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली के जंतर-मंतर स्थित उनकी भूख हड़ताल स्थल से जबरन हटाकर अस्पताल ले जाने के एक दिन बाद, प्रमुख समाचार पत्रों ने रविवार को केवल पुलिस के इस दावे को प्रकाशित किया कि उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया था। अधिकांश समाचार पत्रों ने इस खबर को अपने पहले पृष्ठ पर छापा।

इसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को पृष्ठ के निचले भाग में रख दिया और इसे केवल विपक्षी दलों की टिप्पणियों तक सीमित कर दिया। हिंदी दैनिक अमर उजाला ने इस खबर का उल्लेख अपने पहले पृष्ठ पर नहीं किया। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे पहले पृष्ठ पर प्रमुख स्थान नहीं दिया, लेकिन उसने उल्लेख किया कि वांगचुक को विरोध स्थल से "जबरदस्ती हटाया" गया था।

जहां एक ओर इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस कार्रवाई को पहले पन्ने की खबर के रूप में प्रकाशित किया और कहा कि वांगचुक को अस्पताल में "स्थानांतरित" किया गया था, वहीं तथाकथित प्रमुख समाचार पत्रों ने ज्यादातर पुलिस के दावों पर ध्यान केंद्रित किया और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का जिक्र तक किए बिना पुलिस का बचाव करने का बचकाना प्रयास किया।

गुजरात में बच्ची के अपहरण-हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर, हिरासत से भागने के प्रयास में दो जवानों पर चाकू से किया था हमला

आणंद। गुजरात के आणंद जिले में साढ़े चार वर्षीय बच्ची के कथित अपहरण और हत्या के मामले ने रविवार देर रात नया मोड़ ले लिया, जब मुख्य आरोपी पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान हुई मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने वाहन रुकवाने के बाद अचानक छिपाकर रखा चाकू निकालकर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और मौके से फरार होने का प्रयास किया। इस हमले में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि आरोपी को कई बार आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई, लेकिन वह लगातार हमला करता रहा। इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हिरासत में रहते हुए आरोपी के पास चाकू कैसे पहुंचा और सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई, इसकी भी जांच की जाएगी। दूसरी ओर, बच्ची की हत्या की घटना से क्षेत्र में पहले से ही भारी आक्रोश का माहौल है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत पड़ताल कर रही है। अहमदाबाद रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राघवेंद्र वत्स ने बताया कि मुठभेड़ की घटना रविवार देर रात हुई। उन्होंने कहा कि बच्ची के अपहरण और हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी को स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) की टीम पूछताछ के लिए आणंद शहर ला रही थी। रास्ते में आरोपी ने वाहन रुकवाने के लिए उल्टी आने की बात कही। पुलिसकर्मियों ने जैसे ही वाहन रोका, उसने अचानक छिपाकर रखा चाकू निकाल लिया और पुलिस दल पर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहले दो पुलिसकर्मियों पर चाकू से वार किए, जिससे दोनों घायल हो गए। इसके बाद उसने अंधेरे का फायदा उठाकर भागने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उसे रुकने और आत्मसमर्पण करने की कई बार चेतावनी दी, लेकिन उसने कथित रूप से हमला जारी रखा। पुलिस का कहना है कि परिस्थितियों को देखते हुए एक उपनिरीक्षक ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जो आरोपी को लगी। गंभीर रूप से घायल आरोपी को तत्काल करमसद के अस्पताल ले जाया गया, जहां सोमवार तड़के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सुरेश परमार (करीब 20 वर्ष) के रूप में हुई है। वह आणंद जिले के बोरसद कस्बे का निवासी था और उस पर वसाड क्षेत्र से साढ़े चार वर्ष की एक बच्ची के अपहरण और हत्या का आरोप था। पुलिस के अनुसार आरोपी को रविवार देर शाम बोरसद ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसे आगे की जांच के लिए स्थानीय अपराध शाखा को सौंपा गया था। इस हृदयविदारक मामले की शुरुआत शनिवार रात हुई थी। पुलिस के अनुसार साढ़े चार वर्ष की बच्ची अपने माता-पिता के साथ वसाड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सो रही थी। बच्ची के माता-पिता प्रवासी मजदूर हैं और काम की तलाश में वहां ठहरे हुए थे। शनिवार रात लगभग 9:15 बजे बच्ची अचानक लापता हो गई। परिवार ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस ने तत्काल खोज अभियान शुरू किया। रविवार तड़के रेलवे पटरियों के पास बच्ची का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर फोरेंसिक टीम को बुलाया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। जांच के दौरान रेलवे स्टेशन के कैमरों में एक युवक बच्ची को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया। फुटेज के आधार पर उसकी पहचान सुरेश परमार के रूप में हुई, जिसके बाद विभिन्न पुलिस टीमों ने उसकी तलाश शुरू कर दी।

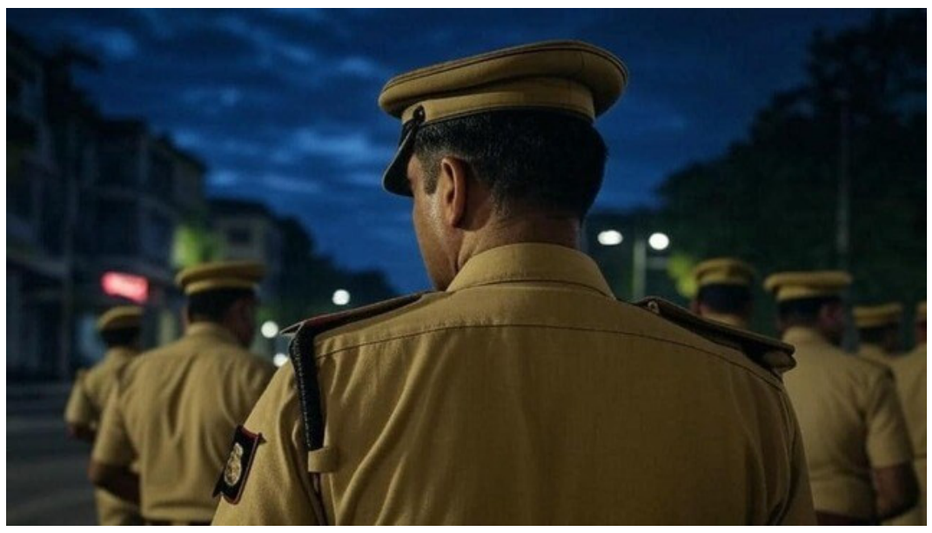

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रेलवे पुलिस, आणंद जिला पुलिस, स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी), विशेष अभियान समूह (एसओजी) और वसाड पुलिस की संयुक्त टीमों ने अभियान चलाया। कई घंटों की तलाश के बाद रविवार देर शाम बोरसद ग्रामीण क्षेत्र से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उससे घटना के संबंध में पूछताछ कर रही थी और आगे की जांच के लिए उसे आणंद लाया जा रहा था, तभी रास्ते में यह घटना हुई।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार घायल दोनों पुलिसकर्मियों का उपचार कराया गया और उनकी स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। साथ ही मुठभेड़ की पूरी घटना का दस्तावेजीकरण किया गया है। घटनास्थल से बरामद साक्ष्यों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मुठभेड़ के बाद पुलिस विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि हिरासत के दौरान आरोपी के पास चाकू कैसे पहुंचा, इसकी अलग से जांच होगी। वरिष्ठ अधिकारियों ने संबंधित पुलिस दल से पूरी रिपोर्ट मांगी है। यदि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बच्ची की हत्या की घटना ने पूरे गुजरात में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों ने दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस का कहना है कि मूल हत्या प्रकरण और मुठभेड़, दोनों मामलों में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी और सभी आवश्यक तथ्य सामने आने के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी।